नई दिल्ली
मंगलवार
17 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 74
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष अश्विनी जोशी 'मोन्टी'...पेज-05

DELHIN/2014/58158

समाज को मार्गदर्शन देने का काम करते...पेज-08

एक नजर

एक फरवरी को पेश होगा बजट, निर्मला सीतारमण ने शुरू कीं प्री-बजट परामर्श' बैठकें

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2027-28 की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए सोमवार से प्री-बजट परामर्श' बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने नई दिल्ली में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो बैठकें कीं। वित्त मंत्रालय के अनुसार सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2027-28 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली 'प्री-बजट परामर्श' बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और डीईए के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य अगले वित्त वर्ष का बजट तैयार करने से पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव और विचार लेना है। दूसरी 'प्री-बजट परामर्श' बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग और मत्स्य पालन विभाग के सचिवों के साथ-साथ कृषि मंत्रालय के भी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। केंद्रीय बजट एक फरवरी, 2027 को पेश किए जाने की संभावना है। देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का आकलन प्रस्तुत करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी या 31 जनवरी, 2027 को पेश किए जाने की संभावना है।

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में किया स्पष्ट- फॉर्म-6 भरने पर कानूनी कार्रवाई नहीं

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने स्पष्ट किया है कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' जमा करने वाले मतदाताओं के खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह बात तब भी लागू होगी, जब उनका नाम पहले की मतदाता सूची में शामिल रहा हो। यह स्पष्टीकरण ईसीआई की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने 14 नवंबर को उच्चतम न्यायालय में एक पूरक हलफनामे के जरिए दिया। यह हलफनामा राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया था।

आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि तीन नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल, फॉर्म 6 मुख्य रूप से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। इस फॉर्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसका नाम पहले किसी मतदाता सूची में शामिल नहीं रहा है। इस कारण, जिन मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण के दौरान सूची से कट गए थे, उन्हें यह डर था कि दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरने पर उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत 'गलत घोषणा' करने का मामला दर्ज हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि आवेदक का नाम पहले किसी मतदाता सूची में दर्ज था। यह कानूनी सुरक्षा केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगी, जिनका नाम वर्तमान में किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और जिन्होंने फॉर्म में अन्य सभी जानकारियां सत्य भरी हैं।

उपराष्ट्रपति का विधायकों से लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान



भुवनेश्वर,एजेंसी। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में ओडिशा की 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। विधायकों से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक वाद-विवाद, विचारपूर्ण चर्चा, विधायी कार्यकुशलता और जन-केंद्रित शासन के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाधी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और विधायकों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने वैशाली की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चोल काल की कुडवोलाई प्रणाली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत इतिहास में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को 'लोकतंत्र की जननी' होने पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने ओडिशा के विधायकों से इस गौरवशाली विरासत के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति ने जोर देते हुए कि चुनावी जीत सार्थक जनसेवा में परिणत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम चुनाव वोटों से जीतते हैं, लेकिन जनता का सम्मान केवल अपनी सेवा से अर्जित कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल वाद-विवाद का मंच नहीं है, बल्कि यहां बनाई गई प्रत्येक नीति, उठाया गया प्रत्येक प्रश्न और पारित किया गया प्रत्येक कानून असंख्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा की प्रगति भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्ष 2036 में एक प्रांत के रूप में ओडिशा के गठन की शताब्दी पूरी होने के अवसर को देखते हुए उन्होंने इस राज्य को विकसित, समृद्ध और समावेशी बनाने में 'विजन ओडिशा 2036' के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विधायक युवाओं के लिए अवसर सृजित करने और विकास का लाभ प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि विचारों में मतभेद जनता और संविधान के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के आड़े नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में हम किसी बात पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर हम सभी को सहमत होना चाहिए और वह है जनता तथा संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता।' उन्होंने कहा कि 'बहस, चर्चा या कभी-कभी व्यवधान का भी परिणाम निर्णय के रूप में सामने आना चाहिए।' उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक वाद-विवाद और रचनात्मक सहयोग का आह्वान किया। निरंतर सीखने और तैयारी के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने विधायकों से विधायी नियमों और प्रक्रियाओं, बजटीय प्रक्रियाओं, समिति प्रणाली, संसदीय परंपराओं तथा नैतिकता से भली-भांति परिचित होने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने विशेष रूप से प्रश्नकाल और शून्यकाल के महत्व को रेखांकित करते हुए इन्हें प्रत्येक विधायक के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों को उठाने के महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने विधायकगों से आग्रह किया कि वे इन महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी को सहयोग दें। उपराष्ट्रपति ने सदन के कामकाज से जुड़े विषयों पर आम सहमति बनाने में कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी- बीएसी) की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समिति के भीतर अधिक सहमति बनने से विधायी कार्यवाही अधिक सुचारु और प्रभावी होगी। विधायी कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के तहत ओडिशा विधानसभा में डिजिटल सदन के उद्घाटन का स्वागत किया। राज्यसभा में डिजिटल मंचों के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से संसदीय दस्तावेज, प्रश्न और बहस अब अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं।

यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, राज्यों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी की बदहाल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सफाई पर भारी भरकम धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है। जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस स्थिति के लिए नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। न्यायालय ने यमुना बेसिन से जुड़े सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2027 को निर्धारित की गई है।



सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि यमुना की खराब सेहत और इसमें गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नाले नदी के किनारे पर बसे क्षेत्रों की लचर नागरिक व्यवस्था का आईना हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने से नदी साफ नहीं होगी, बल्कि औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोकना होगा। न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना तथा प्रमुख नालों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे। यदि किसी राज्य या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने सभी एसटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और बायोगैस संयंत्रों में एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने और लाइव डेटा अपलोड करने का आदेश दिया है। साथ ही सीपीसीबी को हर तिमाही औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान बेंच ने यमुना एक्शन प्लान के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए, जिसमें दिल्ली के जोन 'ओ' के 35 जल निकायों और वेटलैंड्स को अतिक्रमण-मुक्त बताया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के ही दस्तावेजों में इन सभी 35 स्थानों पर अतिक्रमण दर्ज है। न्यायालय ने इस क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखने और नियमनुसार अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

मनीला में भारतीय समुदाय के स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने भारत-फिलीपींस के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों की झलक सराही



नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिलीपींस में भारतीय समुदाय की ओर से किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के साथ-साथ भारत और फिलीपींस को करीब लाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि मनीला में भारतीय समुदाय से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई। समुदाय ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'यह देखकर सुखद लगता है कि हमारे प्रवासी भारतीय भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने के साथ-साथ दोनों देशों को और करीब लाने के लिए भी काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वागत कार्यक्रम में भारत और फिलीपींस के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों की सुंदर झलक देखने को मिली। इस दौरान नौवीं-दसवीं शताब्दी की अगुसान की स्वर्ण तारा प्रतिमा और ऐतिहासिक लगुना ताम्रपत्र अभिलेख की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गईं। ये ऐतिहासिक धरोहरें दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के प्राचीन सांस्कृतिक और समुद्री संपर्कों को दर्शाती हैं। उन्होंने कार्यक्रम के विशेष आकर्षण का जिक्र कर कहा कि दोनों देशों के बच्चों द्वारा पूर्ण कुंभ श्लोक का पाठ किया जाना बेहद खास रहा। इसके बाद बॉलीवुड और भांगड़ा की ऊर्जावान प्रस्तुतियां हुईं। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों और आज के दौर में जारी सांस्कृतिक आदान-प्रदान की जीवंत झलक दिखाई दी।

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग' का औपचारिक विमोचन

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को अपनी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के औपचारिक विमोचन के अवसर पर कहा कि उनके परिवार के बारे में बहुत-सी ऐसी बातें फैलाई गईं, जिनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं था। लोगों के सामने अपनी बात और परिवार से जुड़े अनुभव रखने के लिए उन्होंने यह किताब लिखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में इंदिरा गांधी से मिले संस्कारों, राजीव गांधी की राजनीति में आने को लेकर अपनी आशंकाओं, उनकी मृत्यु के बाद के अनुभवों और भारतीय महिलाओं के नए परिवार में स्वीकार किए जाने के संघर्ष पर भी बात की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' का सोमवार को दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में औपचारिक विमोचन हुआ।

लगातार तीसरे महीने थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.29 फीसदी पर आई



नई दिल्ली,एजेंसी। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटका लगने वाली खबर है। ईंधन एवं बिजली, खाद्य पदार्थों, खनिजों और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से लगातार तीसरे महीने थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.29 फीसदी पर पहुंच गई है, जो सितंबर 2026 में 11.39 फीसदी रहीं। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 8.26 फीसदी रही, जो पिछले अक्टूबर महीने 8.14 फीसदी थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई पिछले महीने अक्टूबर में 11.69 फीसदी रही, जबकि सितंबर में यह 10.28 फीसदी थी। इसके साथ ही खनिजों में कीमतों में वृद्धि की दर 12.64 फीसदी रही, जो सितंबर में 9.51 फीसदी थी। मंत्रालय के मुताबिक कुल मिलाकर प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 9.24 फीसदी हो गई, जो सितंबर महीने में 8.67 फीसदी रहीं थी। इसके अलावा ईंधन एवं बिजली की महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 32.84 फीसदी हो गई, जो पिछले महीने सितंबर में 25.85 फीसदी रही थी। इसके साथ ही विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई 9.54 फीसदी रही, जबकि सितंबर में यह 9.76 फीसदी थी। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजहों में खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य पदार्थ, बुनियादी धातुओं का विर्माण, रसायन एवं रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण, खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर-खाद्य वस्तुएं, कपड़ा विनिर्माण तथा रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण शामिल हैं। पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) अक्टूबर में 6.09 फीसदी रही थी। ये दो साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ऊपरी तय सीमा से अधिक रही है।

उत्तर प्रदेश में सपा के साथ सीट बंटवारे पर कांग्रेस की खरगे के आवास पर बैठक



नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठन और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद खरगे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन चर्चा हुई। आने वाले चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे। प्रदेश की जनता सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है। कांग्रेस, इंडी गठबंधन के साथ मिलकर प्रदेश की जनता के सामने मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 17 नवंबर को बैठक होनी है। इसमें दोनों दलों के नेता सीटों की संख्या और गठबंधन के फार्मूले पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की ओर से अब तक 181 सीटों पर दावेदारी की बात सामने आई है। सपा का जोर सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को आधार बनाने पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में कांग्रेस की 181 सीटों पर दावेदारी का उल्लेख किया था। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम बराबरी और सम्मान के आधार पर गठबंधन की बात कह चुके हैं।

जनगणना के दूसरे चरण के लिए स्व-गणना शुरू

● 30 नवंबर तक ऑनलाइन दे सकेंगे विवरण



नई दिल्ली,एजेंसी। जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में सोमवार से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन राज्यों और क्षेत्रों के निवासी 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे।

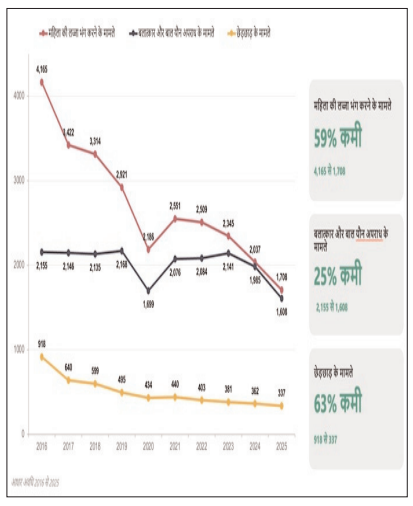
आधिकारिक जानकारी के अनुसार घर-घर गणना के बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलाया जाएगा। इन राज्यों और क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है। स्व-गणना में भाग लेने के लिए निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए पहले चरण के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। पोर्टल पर परिवार और व्यक्तिगत विवरण से जुड़े अधिसूचित 40 सवालों के जवाब देने होंगे। सफलतापूर्वक जानकारी जमा करने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) जारी होगी, जिसे बाद में घर आने वाले जनगणनाकर्मी को उपलब्ध कराना होगा। जनगणना के दौरान स्व-गणना की सुविधा लेने वाले परिवारों के यहां भी जनगणनाकर्मी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंचेंगे। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की होगी, उनके विवरण जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर दर्ज करेंगे। इस प्रकार स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद सभी आवंटित क्षेत्रों में घर-घर गणना की प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। इसके बाद एक से पांच मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इनके लिए जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानसूचीकरण एवं आवास गणना (एचएलओ) मणिपुर को छोड़कर देश के सभी 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। देश में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यमों से संचालित की जा रही है। इसके तहत स्व-गणना को एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में शुरू किया गया है। यह सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब आधारित व्यवस्था 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध में गिरावट, छेड़छाड़ के मामले 63 प्रतिशत घटे

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2016 से 2025 के बीच छेड़छाड़ के मामलों में 63 प्रतिशत, महिला की लज्जा भंग करने के मामलों में 59 प्रतिशत और दुष्कर्म एवं बाल यौन अपराधों के मामलों में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों के साथ अपराधों की जांच और अभियोजन में तेजी लाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2016 में महिला की लज्जा भंग करने के 4,165 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2025 में घटकर 1,708 रह गए। इसी अवधि में दुष्कर्म और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के मामले 2,155 से घटकर 1,608 और छेड़छाड़ के मामले 918 से कम होकर 337 रह गए।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तीन महीने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, आपातकालीन सहायता और अपराधों की जांच



एवं सुनवाई में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक पार्कों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए छह हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कुल 19,822 अंधेरे और असुरक्षित स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1,635 पार्कों का ऑडिट पूरा किया गया है। इनमें चारदीवारी, बाड़ और प्रकाश व्यवस्था बेहतर की जा रही है। सभी पार्कों की चारदीवारी और बाड़ लगाने का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112 का औसत प्रतिक्रिया समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटाकर आठ मिनट दो सेकंड कर दिया गया है। इसके अलावा 178 पिंक स्कूटी और 35 पूरी तरह महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी फिलहाल 17.3 प्रतिशत है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। राजधानी में 125 पिंक बूथों पर प्रतिदिन औसतन 308 शिकायतकर्ता पहुंच रहे हैं। हवाई अड्डों, रेलवे और मेट्रो पुलिस थानों में 24 घंटे महिला सहायता डेस्क संचालित हैं। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई भी गठित की गई है। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार रोकने के लिए चलाए जा रहे 'शिष्टाचार' अभियान के तहत 17,387 अभियान चलाए गए, जिनमें 1,24,010 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22,662 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से लगभग 15.9 लाख लोगों तक पहुंच बनाई गई। आत्मरक्षा कार्यक्रमों में 5.7 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि बाल सुरक्षा से जुड़ी पहलों में 3.4 लाख लोग शामिल हुए। बालिका स्कूलों, छात्रावासों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में हर सप्ताह लगभग 3,514 दौरे किए जा रहे हैं। इनमें बीट पुलिसकर्मियों के 1,869 और थाना प्रभारियों के 882 दौरे शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए 25 विशेष अदालतें कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त अदालतें स्थापित की जा रही हैं। जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर तक बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 81 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। दो महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने के निर्धारित समय का पालन 94 प्रतिशत मामलों में किया गया है। वर्ष 2025 में इन अपराधों के मामलों में 99 प्रतिशत आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। अज्ञात आरोपितों से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने से आरोपपत्र दाखिल होने तक का औसत समय 59 दिन रहा। नोएडा बस मामले में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर मामले में 29 दिन में आरोपपत्र दाखिल किए गए। आदतन यौन अपराधियों की जमानत रद्द कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत मामलों में डीएनए जांच कराई जा रही है।

विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्र निर्माण में मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर दिया जोर

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्र निर्माण में मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नैतिकता, प्रतिबद्धता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना के बिना प्राप्त ज्ञान का उपयोग विनाशकारी कार्यों में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को राष्ट्र के लिए सार्थक योगदान देने के योग्य बनाना भी है। यह बात उन्होंने सोमवार को ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के अंतर्गत मैत्रीबोध परिवार द्वारा आयोजित ट्रांसफॉर्म भारत समिट को संबोधित करते हुए कही। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान जहां शारीरिक बीमारियों का उपचार करता है, वहीं आध्यात्मिकता मन के द्वंद्व और आंतरिक पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। उन्होंने मैत्री दादा की सोच और मैत्रीबोध परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के बेहतर निर्माण के लिए व्यक्ति के संपूर्ण विकास, मूल्य आधारित शिक्षा और युवा नेतृत्व को महत्व देना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान और जानकारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके माध्यम से नैतिकता, संस्कार, चरित्र, अनुशासन और सेवा भाव का भी विकास होना चाहिए। विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बोलते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज के युवा ही इस राष्ट्रीय संकल्प के वास्तविक लाभार्थी हैं, क्योंकि 2047 में भारत के विकसित राष्ट्र बनने के बाद देश को आगे ले जाने का नेतृत्व और जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी के लिए युवाओं को आज से ही तैयार होना होगा, ताकि 2047 में भारत के विकसित राष्ट्र बनने तक युवा पीढ़ी देश का नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण, देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना विकसित होनी चाहिए, जिससे वे अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग राष्ट्र की प्रगति और समाज के कल्याण के लिए कर सकें। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा की युवा संपर्क कार्यक्रम का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर में आमंत्रित किया जाता है, ताकि वे भारत की लोकतांत्रिक और संसदीय विरासत को करीब से समझ सकें। पुराने सचिवालय का भारत के राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से जुड़ाव, प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट और श्री विट्ठलभाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता और लोकतंत्र अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग से प्राप्त हुए हैं।

राहुल गांधी की राजनीति विदेशी समर्थन जुटाने तक सिमटी: तरुण चुग

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं सांसद तरुण चुग ने हैदराबाद में आयोजित समिट के घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेता की राजनीति अब विदेशी दर्शकों के सामने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय छवि को बदनाम करके अपने राजनीतिक आरोपों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने तक सिमट गई है। उन्होंने कहा कि भारत समिट के नाम पर कांग्रेस ने एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन को अपनी राजनीतिक हताशा प्रदर्शित करने और भारत की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर हमला करने का मंच बना दिया है। चुग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत को ऐसा देश बताने का प्रयास करना, जहां लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटनाक्रम की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारत समिट के मंच से कांग्रेस का नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' दोहराया और राहुल गांधी तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को हंसते और तालियां बजाते देखा गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत का अपमान करता है, तो उस पर हंसी किस बात की आती है?

मुख्यमंत्री ने छठव्रतियों के साथ उगते सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया

शबाना बेगम सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाथी घाट पर छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार को बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं के साथ उगते सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर चार दिवसीय कठिन व्रत का समापन किया। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं के बीच मुख्यमंत्री ने भी पूरे उत्साह के साथ छठ महापर्व की परंपराओं में भागीदारी की और सभी को पर्व की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पूरी तरह पूर्वांचल की लोक संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगी नजर आईं। पारंपरिक परिधान में सजी मुख्यमंत्री ने छठ व्रती माताओं और बहनों के साथ मिलकर छठ के पारंपरिक गीत गाए और उनके साथ इस पावन पर्व की खुशियां साझा कीं। उन्होंने छठ व्रती महिलाओं के साथ पारंपरिक रस्मों में भाग लिया और सिंदूर लगाकर उनके साथ पर्व की खुशियां साझा कीं और छठी मैया का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने व्रतियों से मुलाकात कर उनका अभिवादन



किया और सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लाखों भाई-बहनों के लिए आस्था और भावनाओं से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। आज यमुना के घाटों पर पूरा समाज एक साथ छठी मैया की आराधना कर रहा है। पूर्वांचल के लोगों ने अपनी मेहनत और योगदान से दिल्ली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वे दिल्ली परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी संस्कृति, परंपराओं व त्योहारों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने छठी मैया के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद देश और दिल्ली के सभी नागरिकों पर बना रहे। ताकि विकसित भारत और विकसित दिल्ली का संकल्प साकार हो तथा देश का हर परिवार सुख, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त करे। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को सुबह घाटों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो ने विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की। उषा अर्घ्य के पावन अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4:30 बजे से शुरू की गईं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वांचली परिवारजनों ने दिल्ली को केवल अपना घर ही नहीं बनाया, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं से इसे और भी समृद्ध किया है।

इमारतें ढहने की घटनाएं, जहरीली यमुना और दमघोंटू हवा ने खोली रेखा गुप्ता सरकार की पोल : देवेंद्र यादव

- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने यमुना सफाई के सरकारी दावों पर खड़े किए सवाल, प्रदूषण और अवैध निर्माण पर सरकार को घेरा



सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में लगातार हो रही इमारत ढहने की घटनाओं, गंभीर वायु प्रदूषण और यमुना के दूषित पानी को लेकर भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिगड़ती नागरिक व्यवस्थाओं ने सरकार की कार्यप्रणाली और विकास के दावों की वास्तविकता उजागर कर दी है। सरकार दिल्ली को 2047 तक विकसित बनाने की बात कर रही है, जबकि वर्तमान में राजधानी के नागरिक बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छ पर्यावरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं देवेंद्र यादव ने कहा कि पहाड़गंज में निर्माणाधीन इमारत की छत का स्लैब गिरने से आठ लोगों का घायल होना और इससे पहले 5 नवंबर को चावड़ी बाजार के हौज काजी क्षेत्र में इमारत ढहने से सात लोगों की मौत होना बेहद गंभीर घटनाएं हैं। लगातार हो रहे ऐसे हादसे अवैध निर्माण, अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव, कमजोर नींव, पुराने भवनों और एमसीडी तथा दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों की कथित लापरवाही पर सवाल खड़े करते हैं।

यमुना की सफाई के दावों पर उठाए सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यमुना के जहरीले और प्रदूषित पानी को लेकर चिंता जताना दिल्ली कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों को मजबूती देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे किए, लेकिन नदी की वास्तविक स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि सफाई पर इतना पैसा खर्च हुआ है तो उसका वास्तविक परिणाम कहां है और सरकारी खजाने से खर्च की गई राशि का हिसाब कौन देगा? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विज्ञापन और जनसंपर्क अभियानों के जरिए यमुना की सफाई की तस्वीर पेश करने पर अधिक ध्यान दिया, जबकि जमीनी स्तर पर प्रदूषण की समस्या जस की तस बनी हुई है।

छठ पूजा के दौरान भी श्रद्धालुओं को नहीं मिली राहत

देवेंद्र यादव ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान लाखों पूर्वांचल के श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं को प्रदूषित यमुना के पानी में पूजा-अर्चना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री आईटीओ के बजाय सोनिया विहार में छठ पूजा के अवसर पर पहुंचतीं तो उन्हें नदी के पानी की वास्तविक स्थिति का अंदाजा होता। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया विहार में श्रद्धालुओं को गंदे और बदबूदार पानी के बीच छठ पूजा की परंपराएं निभानी पड़ीं। कई घाटों पर पर्याप्त रोशनी और जनसुविधाओं का भी अभाव रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को धार्मिक आस्था के साथ-साथ श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी चिंता करनी चाहिए।

वायु प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं पर भी सरकार घिरी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले दो वर्षों से गंभीर वायु और जल प्रदूषण का सामना कर रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, टूटी सड़कें, जगह-जगह कूड़े के ढेर और जर्जर नागरिक ढांचा लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार प्रदूषण नियंत्रण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के मामले में कोई ठोस उपलब्धि नहीं दिखा पाई है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बार-बार इमारतों का ढहना और प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति प्रशासनिक निगरानी तथा जवाबदेही की कमी को दर्शाती है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के पास जनता की समस्याओं का समाधान देने के बजाय बयानबाजी करने के अलावा कोई ठोस जवाब नहीं है। देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार से मांग की कि यमुना की सफाई पर खर्च की गई धनराशि का सार्वजनिक हिसाब दिया जाए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा अवैध निर्माण और जर्जर इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

एमसीडी के फास्टट्रैक पार्किंग टेंडर पर उठे सवाल, 12 पार्किंग स्थलों की मासिक लाइसेंस फीस 99 लाख रुपये से अधिक!

एस.मलिक, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) की पार्किंग व्यवस्था को लेकर फास्टट्रैक पार्किंग टेंडर का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया है। निगम के Remunerative Project Cell द्वारा जारी Annexure-1 में दिल्ली के 12 सार्वजनिक पार्किंग स्थलों की सूची दी गई है। इस सूची में पार्किंग स्थलों के नाम, संबंधित जोन, रिजर्व मंथली लाइसेंस फीस (RMLF) और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) का विवरण दर्ज है। दस्तावेज के अनुसार, इन सभी 12 पार्किंग स्थलों की निर्धारित मासिक RMLF का कुल योग 99,01,396 रुपये है, जबकि कुल EMD 23,76,334 रुपये निर्धारित है। इस सूची में तिमारपुर ट्रक एवं बस पार्किंग की मासिक RMLF सबसे अधिक 33,58,627 रुपये दर्ज है। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद पार्किंग संचालन, निगम को मिलने वाले राजस्व, ठेकेदारों की जवाबदेही और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं।

तिमारपुर ट्रक एवं बस पार्किंग की RMLF सबसे ज्यादा 33.58 लाख रुपये; FASTag व्यवस्था अनिवार्य, दो पार्किंग स्थलों के लिए FIRE NOC की शर्त भी लागू।

ANNEXURE - 1: LIST OF PUBLIC PARKING SPACES FOR FASTag PARKING TENDER

Sr. no.	NAME OF PARKING SITE	ZONE	RMLF (INR)	EMD (INR)
1	Infront of Old Delhi Railway Station	CITY SP	1766953	424069
2	Timarpur Truck & Bus Parking	CIVIL LINES	3358627	806070
3	Dr. Keshav Baliram Hedgewar, 52 Block Old Rajender Place	KAROL BAGH	401095	96263
4	Qutub Road Near Tanga Stand Sadar Bazar	CITY SP	502000	120480
5	Covered Parking Mandoli Extension	SHAHDARA NORTH	305805	73393
6	ABD Block Dilshad Colony	SHAHDARA NORTH	624301	149832
7	F-Block, Mansarover Garden, Near Water Park	KAROL BAGH	481579	115579
8	Parking Lot-E Plot no. 9A, Distt. Centre, Rajender Place (Multilevel Upper Ground)	KAROL BAGH	424000	101760
9	Vardhman Master Plaza Gazipur	SHAHDARA SOUTH	302652	72636
10	Near Max Hospital Milan Vihar	SHAHDARA SOUTH	815862	195807
11	Infront of Plot no. 5 to 9 Erose Tower Distt. Centre Laxmi Nagar	SHAHDARA SOUTH	474579	113899
12	Infront of Plot no. 17-19, Rajender Place (MLUG)	KAROL BAGH	443943	106546

* Note 1: *The contractot shall implement RFID based FASTag technology for manless/cashless operator of the parking site, whenever, asked for. Non-compliance may lead to termination of the contract.*

* Note 2 : *The possession will be handed over after procurement of FIRE NOC of parking sites at Serial number 8 & 12 of above table.*

Assistant Commissioner
Ramunerative Project Cell, MCD

12 पार्किंग स्थलों की सूची में किसकी कितनी फीस?

एमसीडी के Annexure-1 में शामिल पार्किंग स्थलों का विवरण इस प्रकार है:

1. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने: सिटी एसपी जोन, RMLF 17,66,953 रुपये और EMD 4,24,069 रुपये।

2. तिमारपुर ट्रक एवं बस पार्किंग: सिविल लाइंस जोन, RMLF 33,58,627 रुपये और EMD 8,06,070 रुपये।

3. डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार, 52 ब्लॉक पुराना राजेंद्र प्लेस: करोल बाग जोन, RMLF 4,01,095 रुपये और EMD 96,263 रुपये।

4. कुतुब रोड, टांगा स्टैंड के पास, सदर बाजार: सिटी एसपी जोन, RMLF 5,02,000 रुपये और EMD 1,20,480 रुपये।

5. कवर्ड पार्किंग, मंडोली एक्सटेंशन: शाहदरा नॉर्थ जोन, RMLF 3,05,805 रुपये और EMD 73,393 रुपये।

6. एबीडी ब्लॉक, दिलशाद कॉलोनी: शाहदरा नॉर्थ जोन, RMLF 6,24,301 रुपये और EMD 1,49,832 रुपये।

7. एफ-ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, वाटर पार्क के पास: करोल बाग जोन, RMLF 4,81,579 रुपये और EMD 1,15,579 रुपये।

8. पार्किंग लॉट-ई, प्लॉट नंबर 9ए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेंद्र प्लेस: करोल बाग जोन, RMLF 4,24,000 रुपये और EMD 1,01,760 रुपये।

9. वर्धमान मास्टर प्लाजा, गाजीपुर: शाहदरा साउथ जोन, RMLF 3,02,652 रुपये और EMD 72,636 रुपये।

10. मैक्स हॉस्पिटल, मिलन विहार के पास: शाहदरा साउथ जोन, RMLF 8,15,862 रुपये और EMD 1,95,807 रुपये।

11. इरोस टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, प्लॉट नंबर 5 से 9 के सामने: शाहदरा साउथ जोन, RMLF 4,74,579 रुपये और EMD 1,13,899 रुपये।

12. प्लॉट नंबर 17-19 के सामने, राजेंद्र प्लेस (MLUG): करोल बाग जोन, RMLF 4,43,943 रुपये और EMD 1,06,546 रुपये।

तिमारपुर पार्किंग की RMLF सबसे ज्यादा

दस्तावेज में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक तिमारपुर ट्रक एवं बस पार्किंग की RMLF 33.58 लाख रुपये से अधिक है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग की फीस 17.66 लाख रुपये से अधिक है। वहीं मैक्स हॉस्पिटल, मिलन विहार के पास पार्किंग की RMLF 8.15 लाख रुपये से अधिक दर्ज है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमसीडी की पार्किंग व्यवस्था निगम के लिए कितना महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हो सकती है। ऐसे में पार्किंग से होने वाली वास्तविक वसूली और निगम के खाते में जमा होने वाली राशि का पारदर्शी रिकॉर्ड होना जरूरी है।

FASTag आधारित पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य

दस्तावेज के नोट नंबर-1 में स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध के तहत पार्किंग स्थलों पर RFID आधारित FASTag तकनीक लागू करनी होगी। इसका उद्देश्य पार्किंग ऑपरेटर का संचालन बिना नकदी और बिना मानवीय हस्तक्षेप के करना है। दस्तावेज में यह भी चेतावनी दी गई है कि इस शर्त का पालन नहीं करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सभी 12 पार्किंग स्थलों पर FASTag आधारित व्यवस्था लागू की गई है? क्या प्रत्येक वाहन की एंट्री और पार्किंग शुल्क का डिजिटल रिकॉर्ड निगम के पास उपलब्ध है? इसकी निगरानी कौन कर रहा है?

दो पार्किंग स्थलों पर FIRE NOC के बाद ही मिलेगा कब्जा

Annexure-1 के नोट नंबर-2 में क्रम संख्या 8 और 12 पर दर्ज पार्किंग स्थलों के संबंध में विशेष शर्त रखी गई है। इसके अनुसार इन दोनों स्थलों का कब्जा FIRE NOC प्राप्त होने के बाद ही सौंपा जाएगा। इनमें राजेंद्र प्लेस के डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित पार्किंग लॉट-ई, प्लॉट नंबर 9ए और प्लॉट नंबर 17-19 (MLUG) शामिल हैं। इस शर्त के मद्देनजर यह जानना जरूरी है कि दोनों पार्किंग स्थलों की FIRE NOC प्राप्त हुई या नहीं और ठेकेदारों को कब्जा किस तारीख को सौंपा गया।

छह महीने के राजस्व का हिसाब भी हो सार्वजनिक

फास्टट्रैक पार्किंग टेंडर की तारीख 8 जुलाई 2026 और आवेदन की अंतिम तारीख 29 जुलाई 2026 बताई गई है। वहीं पुरानी पार्किंग व्यवस्था की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त होने की जानकारी भी सामने आई है।

ऐसे में निगम प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि पुरानी अवधि समाप्त होने के बाद पार्किंग संचालन किस व्यवस्था के तहत जारी रहा। क्या पुराने ठेकेदारों को अनुबंध विस्तार दिया गया था? यदि हां, तो किस अधिकारी की स्वीकृति से? साथ ही संबंधित छह महीने की अवधि में पार्किंग स्थलों से कितनी वसूली हुई, निगम के खाते में कितनी रकम जमा हुई और कितनी राशि बकाया रही, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

निगम प्रशासन से जवाबदेही की मांग

इस मामले में एमसीडी के Remunerative Project Cell, संबंधित जोन के अधिकारियों, राजस्व विभाग और पार्किंग ठेकेदारों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। निगम प्रशासन को टेंडर की पूरी फाइल, पुराने अनुबंध, एक्सटेंशन आदेश, FASTag व्यवस्था की रिपोर्ट, FIRE NOC और पार्किंग से प्राप्त राजस्व का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही सभी 12 पार्किंग स्थलों का वित्तीय ऑडिट कराया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब निगम के दस्तावेज में 12 पार्किंग स्थलों की कुल मासिक RMLF 99 लाख रुपये से अधिक दर्ज है, तो पार्किंग संचालन और वास्तविक राजस्व का पूरा हिसाब जनता के सामने कब आएगा? यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

सद्भावना टुडे इस मामले में एमसीडी प्रशासन का आधिकारिक पक्ष भी प्रकाशित करेगा।

एक नजर

गुरुग्राम : सेक्स रैकेट के आरोपियों को पहले नोटिस दिए, 24 घंटे में वापस लिए

गुरुग्राम। सेंट्रल पार्क ग्रुप कंपनी से जुड़े निदेशकों समेत नौ लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल सेक्स रैकेट संचालित करने और विदेशी महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोपों की जांच के लिए भेजे गए नोटिस पुलिस ने 24 घंटे के भीतर वापस भी ले लिए। शिकायतकर्ता वंशनी फाउंडेशन की डायरेक्टर स्वाति चौधरी ने इसे गलत ठहराया है। एमरल्ड कोर्ट स्थित वंशनी फाउंडेशन की डायरेक्टर स्वाति चौधरी ने कथित इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले की विस्तृत जांच की मांग की थी। स्वाति चौधरी द्वारा दी गई शिकायत संख्या 6410-डीडब्ल्यू दिनांक 06 नवंबर 2026 में रूस, ट्यूनीशिया और दुबई समेत कई देशों में कथित नेटवर्क संचालित तथा गुरुग्राम स्थित प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इस काम के लिए करने का आरोप लगाया था। शिकायत में ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों अमरजीत बख्शी, कवलजीत बख्शी, नूर बख्शी, सनम बख्शी, संजीत बख्शी, शिव बख्शी, चिराग गहलोत, अशोक अग्रवाल और सौरभ भारद्वाज सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए 14 नवंबर 2026 को नोटिस जारी किए। जांच एसीपी उद्योग को सौंपी गई है। इसी बीच कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त उद्योग गुरुग्राम की ओर से इस शिकायत में जारी किए गए नोटिस को 24 घंटे के अंदर तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया। जारी पत्र में पुलिस ने कहा है कि प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से नोटिस तत्काल से वापस भी लिए जाते हैं। इस मामले में किसी को भी उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता का सवाल यह है कि पुलिस ने मामले की जांच तेजी लाने की बजाय भेजे हुए नोटिस वापस क्यों लिए।

पिज्जा स्टोर के मैनेजर से मारपीट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी

फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित डोमिनोज पिज्जा स्टोर के मैनेजर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पानी न दिए जाने पर कुछ युवकों ने स्टोर में घुसकर उसको थप्पड़ मारे। मारपीट स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित का कहना है कि वहां स्टोर पर कुछ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन वो केवल देखते रहे। शिकायत दिए जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया है। उधर, पुलिस का कहना है कि हमें शिकायत मिली है। हम सीसीटीवी फुटेज जांच रहे हैं। जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। स्टोर मैनेजर नितेश कुमार (22) ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं और फिलहाल विनय नगर, सेक्टर-31 में रहते हैं। वह पिछले एक साल से सेक्टर-12 स्थित डोमिनोज आउटलेट में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में नौकरी करते थे। नितेश के मुताबिक, वह एक कर्मचारी के साथ स्टोर में काम कर रहे थे। बाकी तीन कर्मचारी ऑर्डर सप्लाई करने बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अजय नाम का एक व्यक्ति स्टोर पर आया और पानी मांगा। कर्मचारी कम होने और काम में व्यस्त होने के कारण उनकी आवाज अंदर तक नहीं पहुंची। इसी बात को लेकर उसने विवाद शुरू कर दिया। नितेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने युवक को शांत रहने के लिए कहा तो उसने उन्हें थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इसी दौरान युवक के अन्य साथी भी स्टोर के अंदर आ गए और झगड़ा करने लगे। स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद नितेश ने फोन कर पुलिस को सूचना दी। नितेश का आरोप है कि घटना 2 नवंबर की रात की है। तभी पुलिस को फोन कर बुलाया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका दावा है कि पुलिस के सामने भी उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिसकर्मी खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने मामले की लिखित शिकायत भी दी, लेकिन अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। सेंट्रल थाना प्रभारी सतबीर ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कारोबारी की मौत का मामला चार माह बाद हत्या में तब्दील, छह नामजद

फरीदाबाद। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर चादर और फूल बेचने वाले लईक अहमद की मौत अब हत्या के मामले में तब्दील हो गई है। करीब चार महीने तक चली जांच के बाद आई एफएसएल रिपोर्ट में उनके शरीर में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना पुलिस ने हत्या और जहर देने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मृतक की पत्नी रीहाना निजामी ने छह लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया है कि संपत्ति विवाद के चलते उनके पति को साजिश के तहत जहर दिया गया। शिकायत के अनुसार, लईक अहमद और खोरी निवासी नन्ने उर्फ मोहसिन के बीच संपत्ति के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने नन्ने उर्फ मोहसिन, उसकी मां मुनीजा, वकील फखरे आलम, वासिद, सुक्की और दिलबर उर्फ दिलशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस टीम पर फायरिंग व हमले के चार दोषियों को सात-सात साल की कैद

नूंह,एजेंसी। नूंह पुलिस टीम पर फायरिंग कर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने के करीब सात साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 40,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि घटना 9 जुलाई 2019 की है। उस दिन पुन्हाना थाना पुलिस की टीम लुहिंगाकला बस अड्डे के पास एक लूट के मामले में आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मामले से जुड़े चार आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर ऐचवाड़ी गांव की तरफ से



आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने लुहिंगाकला और ऐचवाड़ी गांव के बीच नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवक वहां पहुंचे। पुलिस टीम को सामने देखकर चारों मोटरसाइकिल छोड़कर अलग-अलग दिशाओं में झाड़ियों की ओर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया तो आरोप है कि दो आरोपियों ने देशी कट्टों से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने पीछा कर चारों को काबू कर लिया। पुलिस ने मौके से देशी कट्टे, खाली खोल और दोनों मोटरसाइकिलें भी बरामद की थीं। इस मामले में पुलिस ने इरफान उर्फ ईप्पी निवासी गांधनेर, शौकीन निवासी गांधनेर, आरिफ निवासी गोधोला और लियाकत निवासी मंडोरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 नवंबर को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोषियों को सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ऐसे में चारों दोषियों को अधिकतम सात वर्ष का कारावास भुगतना होगा। करीब सात साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले को पुलिस टीम पर हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गुरुग्राम के सोहना चौक पर 340.78 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

गुरुग्राम। केंद्र सरकार ने गुरुग्राम जिले के सोहना क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात देते हुए सोहना चौक पर 2.75 किलोमीटर लंबे 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 340.78 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने यह राशि मंजूर किए जाने पर केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनएच-919 और एनएच-248ए के जंक्शन पर बनने वाला यह एलिवेटेड कॉरिडोर सोहना में यातायात व्यवस्था को नई गति देगा। इससे गुरुग्राम-नूंह के बीच गुजरने वाले ट्रैफिक को स्थानीय एवं क्रॉस ट्रैफिक से अलग किया जा सकेगा और वाहनों को अधिक सुगम एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। गंगवा ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से सोहना चौक पर यातायात का दबाव कम होगा, सडक़ क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों के समय की बचत होगी। साथ ही, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेस वे से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इस परियोजना से न केवल वर्तमान यातायात व्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भी बेहतर सडक़ कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। रणबीर गंगवा ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सडक़ बुनियादी ढांचे को लगातार नई मजबूती मिल रही है।

गुरुग्रामः गाड़ी का शीशा तोड़ नकदी व कीमती सामान चोरी के दो आरोपी काबू

गुरुग्राम। बंजारा मार्केट के पास खड़ी गाड़ी का शीशा तोडक़र नकदी व कीमती सामान चोरी करने वाले दो आरोपियों को अपराध शाखा सेक्टर-65 की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने सोमवार को बताया कि आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई एक स्कूटी, एक अर्टिगा गाड़ी, तीन मोबाइल फोन व गाड़ी का शीशा तोडऩे का औजार बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार चार नवंबर 2026 को पुलिस थाना सेक्टर-65 की पुलिस टीम को एक पीड़ित ने शिकायत दी। पीड़ित ने बताया कि एक नवंबर 2026 को उसने अपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस गाड़ी को बंजारा मार्केट सेक्टर-56 स्थित व्हेयर एल्स रेस्टोरेंट के पास खड़ा किया था। जब वह वापस आया तो गाड़ी के पीछे बाईं तरफ के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ व गाड़ी में रखा बैग चोरी मिला। बैग में करीब 75,000 रुपये नकद, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, मूल पैन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज थे। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-65 में केस दर्ज किया गया। अपराध शाखा सेक्टर-65 की पुलिस टीम ने 14 नवंबर 2026 को सेक्टर-65 से वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान दक्ष (उम्र 24 वर्ष) निवासी मदनगीर दिल्ली, राजेश (उम्र 32 वर्ष) निवासी मदनगीर दिल्ली के रूप में हुई। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। शाम के समय अपने अन्य साथियों के साथ स्कूटी व कार से गुरुग्राम आते थे। वे रेस्टोरेंट, मार्केट व मॉल के आसपास सुनसान अथवा अंधेरे वाले स्थानों पर खड़ी महंगी गाडिय़ों को निशाना बनाते थे। एक आरोपी आसपास निगरानी रखता था, जबकि दूसरा किसी कठोर वस्तु अथवा कोहनी से गाड़ी का शीशा तोडक़र अंदर रखा बैग व कीमती सामान चोरी कर लेता था। चोरी किए गए सोने के आभूषण व अन्य कीमती सामान को दिल्ली में सस्ते दामों पर बेच देते थे तथा चोरी की नकदी अपने शौक पूरे करने में खर्च करते थे। इस वारदात को भी आरोपियों ने इसी तरीके से अंजाम दिया था। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी राजेश के विरुद्ध चोरी का एक केस पहले से दर्ज है। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई एक स्कूटी, एक अर्टिगा गाड़ी, तीन मोबाइल फोन तथा गाड़ी का शीशा तोडऩे के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक औजार बरामद किया है।

आस्था के महापर्व छठ का उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ समापन

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। लोक आस्था का महापर्व छठ का उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने आज सुबह को समापन किया। छठ व्रत की धूम यमुना और हिंडन नदी के विभिन्न घाटों, सेक्टरों, सोसाइटियों और गांवों में बने कृत्रिम तालाबों में देखने लायक रही। सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही घाट छठ माता के जयकारों से गूजांयमान हो गए। इस अवसर पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। अर्घ्य के बाद व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। एनसीआर में सूर्योदय का समय सुबह 06:44 बजे का रहा। व्रतियों ने सुबह से ही घाटों पर पहुंचकर उषा अर्घ्य की तैयारी पूरी कर ली थी। अर्घ्य के लिए तड़के ही व्रती और उनके परिवारजनों ने सूप-दउरा में ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल समेत पारंपरिक प्रसाद सजा लिया था। छठ पूजा में उषा अर्घ्य का विशेष महत्व है। अर्घ्य के दौरान व्रती सूर्यदेव और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।

उषा अर्घ्य के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया है। छठ व्रत को सकुशल संपन्न कराने के लिए नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस ने भी कमर कसी थी। कल से आज सुबह तक पुलिस के भारी जवान



विभिन्न घाटों पर तैनात रहे। छठ व्रत को लेकर यातायात भी डायवर्ट किया गया था। पुलिस उपायुक्त नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना की अब तक जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि यमुना और हिंडन नदी में गोताखोर और नावों की भी तैनाती की गई थी, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके।

नूंह में श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया हजरत शेख मूसा का 715वां सालाना उर्स पाक

नूंह,एजेंसी। नूंह के अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक हजरत शेख मूसा की दरगाह पर सोमवार को 715वां सालाना उर्स पाक श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पर पहुंचे और हजरत शेख मूसा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। उर्स के अवसर पर दरगाह परिसर में दिनभर रौनक बनी रही। वहीं, आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी पूरे आयोजन के दौरान मुस्तैद नजर आए।

मेवात दरगाह कमेटी के सदस्य मोहम्मद आरिफ सूफी ने बताया कि ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार हजरत शेख मूसा, हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। मान्यता है कि एक बार जब हजरत शेख मूसा अरावली पर्वतमाला से होकर गुजर रहे थे, तो उनका पल्लू झाड़ियों में अटक गया। इसके बाद वे इसी स्थान पर ठहर गए। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसी घटना के चलते इस क्षेत्र का नाम पल्ला पड़ा और यहां उनकी दरगाह स्थापित हुई। मोहम्मद रफीक कादरी ने बताया कि हजरत शेख मूसा की दरगाह धार्मिक आस्था के साथ-साथ अपनी



ऐतिहासिक और अनूठी विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। दरगाह परिसर में एक प्राचीन पानी का कुंड बना हुआ है। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि इस कुंड के पानी को शरीर पर मौजूद मस्सों पर लगाने से राहत मिलती है। हालांकि, यह स्थानीय स्तर पर प्रचलित पारंपरिक मान्यता है। दरगाह परिसर में बनी दो मीनारें भी यहां आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, एक मीनार को हिलाने पर दूसरी मीनार में भी कंपन महसूस होता है। दरगाह की इस अनूठी विशेषता को देखने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचते हैं। मेवात दरगाह कमेटी के सदस्य अली मोहम्मद सूफी ने कहा कि हजरत शेख मूसा की दरगाह पर पिछले 715 वर्षों से उर्स मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह दरगाह क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। सालाना उर्स पाक के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही और दरगाह की रौनक देखते ही बनती है। इस अवसर पर गुलाब नबी आजाद एडवोकेट सहित अन्य लोगों ने भी दरगाह की ऐतिहासिक महत्ता और उर्स की परंपरा पर अपने विचार रखे। 715वें सालाना उर्स पाक के आयोजन ने एक बार फिर मेवात की समृद्ध सूफी परंपरा, आपसी भाईचारे और धार्मिक आस्था की झलक पेश की।

हत्या के मामले में फरार चार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोयडा स्थित थाना रबूपुरा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे चार बदमाशों को बीती रात को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली दो बदमाशों के पैर में लगी है। इन बदमाशों ने 8 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को नहर किनारे फेंक दिया था। पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा जोन श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि थाना रबूपुरा पुलिस रविवार की मध्य रात्रि को यीडा क्षेत्र के सेक्टर 20 के पास चैकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाश वहां से भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पीछा करके घेर लिया। अपने आपको पुलिस से घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। उन्होंने बताया कि आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से दो बदमाश घायल हो गए।

टैक्स लेने में आगे सरकार, बुनियादी सुविधाएं देने में है फिसड्डीः पंकज डावर

गुरुग्राम। टी-ब्लॉक, न्यू पालम विहार, गुरुग्राम। यहां करीब 1500 आलीशान घर हैं। अगर यहां कुछ नहीं है तो वह है सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं। यहां रहने वाले लोग सरकार को हाउस टैक्स, डेवेलपमेंट चार्ज और गार्बेज चार्ज भी दे रहे हैं। इतना कुछ देने के बाद भी लोग सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर के समक्ष अपनी व्यथा रखी तो सरकार के उन बड़े दावों की पोल खुल गई, जो सरकार और अधिकारी रोज एसी कमरों में बैठ जनता के लिए योजनाएं बनाने की बात करते हैं।

पंकज डावर ने कहा कि टैक्स लेने में आगे मगर सुविधाएं देने में फिसड्डी साबित हो रही है सरकार। न्यू पालम विहार टी-ब्लॉक के निवासियों के बीच गुडग़ांव कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर पहुंचे तो लोगों ने अपनी समस्याएं गिनाईं। लोगों का कहना था कि वे गुरुग्राम जैसे स्मार्ट सिटी में नहीं, बल्कि किसी पिछड़े गांव में रह रहे हैं। यहां सुविधाओं के नाम पर उन्हें सरकार के किसी अधिकारी, नेता, मंत्री का आश्वासन तक नहीं मिलता। स्थानीय लोगों पंकज डावर को बताया कि डी-ब्लॉक की सडक़ें कभी बनी ही नहीं। कच्चे रास्तों से ही आना-जाना पड़ता है, जिनमें गहरे गड्ढे उनकी राह में परेशानी बनते हैं। बारिश में तो हालत और भी खराब हो जाती है। गड्ढों में पानी भर जाता है और लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग और बच्चे रोज गिरकर चोटिल हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि नगर निगम हाउस टैक्स वसूलता है, डेवेलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसा लेता है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने सरकार और नगर निगम को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ बड़े-बड़े दावे करती है। गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी, साइबर सिटी कहकर प्रचार किया जाता है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।

कांग्रेस ने वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत चौपाल कार्यक्रम में भाजपा को घेरा

गुरुग्राम। तावडू क्षेत्र में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत सोमवार को एक विशाल चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, एआईसीसी पर्यवेक्षक रोहित चौधरी, रोहतक से विधायक एवं गुरुग्राम जिला पर्यवेक्षक भारत भूषण बतरा ने शिरकत की।

हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि आज देश का संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है। जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ हर नागरिक को खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह वोट बचाओ देश बचाओ अभियान सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की एक बड़ी मुहिम है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे देश के संविधान, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा का युवा, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार का ध्यान इन बुनियादी मुद्दों से भटका हुआ है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के हक की लड़ाई सडक़ से लेकर सदन तक पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पर्यवेक्षक रोहित चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब घर-घर जाकर जनता को जागरुक करना होगा। जिला पर्यवेक्षक एवं विधायक भारत भूषण बतरा ने रोहतक और गुरुग्राम जिलों के संगठनात्मक ढांचे पर बात करते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा। ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा कि भाजपा शासन में न केवल हरियाणा, अपितु पूरे देश की जनता परेशान हैं। कांग्रेस ने एसआईआर का मुद्दा उठाकर भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब भाजपा तिलमिला रही है।

हाफिज-ए-कुरान बने मुहम्मद रिहान का पैतृक गांव घासेड़ा में हुआ सम्मान

नूंह। नूंह जिले के गांव घासेड़ा के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र मुहम्मद रिहान ने कुरान-ए-पाक को हिफ्ज (कंठस्थ) कर अपने परिवार, गांव और शिक्षकों का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर पैतृक गांव घासेड़ा की मस्जिद मेदखा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने हाफिज-ए-कुरान बने मुहम्मद रिहान और उनके पिता मुहम्मद कासिम का फूल-मालाएं पहनाकर तथा नकद पुरस्कार देकर सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि मुहम्मद रिहान ने गांव मेवली स्थित मदरसा ईशा अतुल इस्लाम में शिक्षा ग्रहण करते हुए कुरान-ए-पाक को हिफ्ज करने की उपलब्धि हासिल की है। इसी खुशी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता औसाफ नंबरदार ने की। समारोह में गांव के गणमान्य लोगों और समाज के मौजिज व्यक्तियों ने भाग लेकर रिहान की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कुरान-ए-पाक को हिफ्ज करना बड़ी धार्मिक और शैक्षणिक उपलब्धि है। इसके लिए निरंतर मेहनत, लगन और अनुशासन की आवश्यकता होती है। मुहम्मद रिहान के पिता मुहम्मद कासिम और भाई रिजवान अली ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर



करते हुए कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का अवसर है। कार्यक्रम में औसाफ नंबरदार, उमर मुहम्मद, मियांजी आस मुहम्मद, तौफीक खान और खालिद मेवाती सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने हाफिज मुहम्मद रिहान, उनके पिता मुहम्मद कासिम, मदरसा संचालक मौलाना अरशद और कारी अब्दुल बारी को मुबारकबाद पेश की।

राष्ट्रीय प्रेस दिवसः पत्रकारिता, नैतिकता और लोकतंत्र की परीक्षा

योगेश कुमार गोयल



अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने तथा उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक प्रतिष्ठान के रूप में भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने तथा सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत में प्रथम प्रेस आयोग ने 1956 में एक समिति की कल्पना की थी और 10 वर्ष बाद 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की, जिसने 16 नवम्बर 1966 को अपना कार्य शुरू किया। उसी के बाद से प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय प्रेस परिषद देश में स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में सभी पत्रकारिता गतिविधियों की निगरानी करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि देश में प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित न हो। राष्ट्रीय प्रेस दिवस वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से देश में प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां प्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, वहीं स्वतंत्रता के बाद भी अनेक अवसरों पर सिद्ध होता रहा है कि प्रेस के बिना भारतीय लोकतंत्र अधूरा है। पत्रकार को समाज का ऐसा आईना माना जाता रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाता है। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी 'संसद' की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने अथवा जागृत करने के लिए जन-संचार का एक सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वत: ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को दुनिया की कई महान् हस्तियों ने अपने-अपने शब्दों में रेखांकित किया है। पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के शब्दों में कहें तो प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना तथा उन्हें सही ढ़ंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के मुताबिक हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जिसे खोये बिना सीमित नहीं किया जा सकता। अमेरिका के जाने-माने समाचार प्रस्तोता और विख्यात पत्रकार वाल्टर क्रोनकाइट का कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि एक राष्ट्र, जो अपने लोगों को एक खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह एक ऐसा राष्ट्र है, जो अपने लोगों से डरता है। ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता, लेखक तथा दो बार प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन डिसरायली का कहना था कि प्रेस न केवल स्वतंत्र है बल्कि शक्तिशाली भी है और वह शक्ति हमारी है। नेल्सन मंडेला ने भी एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र के स्तंभों में से एक बताया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को एक ऐसा अनमोल विशेषाधिकार बताया था, जिसे कोई भी देश नहीं छोड़ सकता।

प्रेस से जुड़े लोगों के कंधों पर समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और चूंकि प्रेस को समाज का दर्पण माना गया है, अत: उस दर्पण में हम जनता को जो कुछ दिखाएंगे, वही उसे नजर आएगा। इसलिए प्रेस जगत के लोगों से समाज के हर वर्ग को यही उम्मीद होती है कि उनका चरित्र अच्छा हो, उनके लेखन में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो तथा वे ऊंचे आचार सिद्धांतों को अपनाएं। कानून व्यवस्था की खामियों को प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना, पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों, अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पर्दाफाश करना, समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पर्दाफाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि प्रेस के निम्नलिखित प्रमुख दायित्व माने गए हैं लेकिन यदि पत्रकार स्वयं भ्रष्ट व गैर जिम्मेदार होंगे तो न वे निष्पक्षता के साथ अपनी बात कहने में सक्षम होंगे और न ही समाज के सामने कोई आदर्श तस्वीर प्रस्तुत कर सकेंगे।पत्रकार जनता का ऐसा प्रतिनिधि होता है, जो जनता द्वारा चुना तो नहीं जाता लेकिन उसकी समस्याओं को उसके चुने गए प्रतिनिधियों के सामने समाधान के लिए प्रस्तुत करने का बड़ा माध्यम होता है। अत: यदि प्रेस प्रतिनिधि समाज के कमजोर व शोषित वर्ग की आवाज उठाने के बजाय निहित स्वार्थों के चलते केवल सत्ता से ही प्रेम संबंध बनाने के प्रयासों में लगा रहेगा तो यह प्रेस की विश्वसनीयता के लिए ही घातक सिद्ध होता है। बहरहाल, राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा, समृद्धि व विकास, राष्ट्रीय अखंडता तथा जन जागरण की ओर अग्रणी रहने हेतु प्रेस को अपनी बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भारत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 (डाक या प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक चैनल) पर औपचारिक आपत्ति दर्ज करा रखी है और अनुच्छेद 8 के तहत राजनयिक तामील केवल अनुरोध करने वाले देश के अपने नागरिकों तक सीमित है। सभी रास्ते बंद होने पर पन्नू ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 का सहारा लिया, जो प्राप्तकर्ता देश के घरेलू कानून द्वारा अनुमत तामील के तरीकों को सुरक्षित रखता है। इसी आधार पर 9 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने पन्नू को 30 नवंबर तक प्रस्तावित सर्विस पैकेट जमा करने का निर्देश दिया, ताकि कोर्ट क्लर्क उसे दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स को भेज सके। अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत कोई भी अदालत सीधे दूसरे देश की संप्रभु सीमा में अपने आदेश लागू नहीं कर सकती, इसलिए दो देशों की अदालतों के बीच संवाद राष्ट्रों के सौहार्द और संधियों के माध्यम से होता है। 1965 के हेग सेवा अभिसमय के अनुच्छेद 2 से 6 के तहत एक अदालत प्राप्तकर्ता देश के नामित केंद्रीय प्राधिकरण (भारत में विधि एवं न्याय मंत्रालय) को अनुरोध पत्र भेजती है, जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राष्ट्रीय संप्रभुता व सुरक्षा की जांच के बाद दस्तावेज स्थानीय अदालत को अग्रसारित करता है, जबकि अभिसमय का अनुच्छेद 19 घरेलू कानून की अनुमति होने पर विदेशी अदालत के क्लर्क को सीधे संबंधित स्थानीय अदालत को समन भेजने का विकल्प देता है।

न्यूयॉर्क से दिल्ली तक समन पहुंचाने का दांव-पेंच

अभिषेक शुक्ल



फरवरी 2025 की एक सर्द शाम वाशिंगटन डी.सी. के अति-सुरक्षित 'ब्लेयर हाउस' के बाहर सन्नाटा पसरा है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ठहरे हुए हैं। तभी एक प्राइवेट प्रोसेस सर्वर हाथ में एक मोटा भूरा लिफाफा लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मी उसे वहीं रोक देते हैं। तीन बार नाकाम होने के बाद निराश सर्वर उस लिफाफे को ब्लेयर हाउस से 100 फीट दूर स्थित एक 'स्टारबक्स' कैफे में छोड़कर मान लेता है कि उसका काम हो गया, मगर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने इस 'कॉफी-शॉप तामील' को 3 मार्च 2025 को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि कानून की दुनिया में 'समन' या 'कानूनी नोटिस' महज डाक का एक लिफाफा नहीं होता, बल्कि यह न्याय के बुनियादी सिद्धांत 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष को भी सुने जाने का अधिकार) का वाहक है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की कानूनी टीम ने सितंबर 2024 में दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन तामील कराने के लिए हर संभव रास्ता आजमाया है। 1965 के हेग सेवा अभिसमय के तहत भारत ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) को अपना केंद्रीय प्राधिकरण नामित किया है। पन्नू ने 2024 में इस मंत्रालय के जरिए समन भेजने की कोशिश की, लेकिन मंत्रालय ने यह कहते हुए अनुरोध लौटा दिया कि ये समन हेग कन्वेंशन की निर्धारित श्रेणियों में नहीं आते।

इसके बाद पन्नू ने भारतीय अधिकारियों व वकीलों को ई-मेल करने, अखबारों में प्रकाशन कराने और राजनयिक माध्यमों से तामील की अनुमति मांगी। अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भारत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 (डाक या प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक चैनल) पर औपचारिक आपत्ति दर्ज करा रखी है और अनुच्छेद 8 के तहत राजनयिक तामील केवल अनुरोध करने वाले देश के अपने नागरिकों तक सीमित है। सभी रास्ते बंद होने पर पन्नू ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 का सहारा लिया, जो प्राप्तकर्ता देश के घरेलू कानून द्वारा अनुमत तामील के तरीकों को सुरक्षित रखता है। इसी आधार पर 9 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने पन्नू को 30 नवंबर तक प्रस्तावित सर्विस पैकेट जमा करने का निर्देश दिया, ताकि कोर्ट क्लर्क उसे दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स को भेज सके। अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत कोई भी अदालत सीधे दूसरे देश की संप्रभु सीमा में अपने आदेश लागू नहीं कर सकती, इसलिए दो देशों की अदालतों के बीच संवाद राष्ट्रों के सौहार्द और संधियों के माध्यम से होता है। 1965 के हेग सेवा अभिसमय के अनुच्छेद 2 से 6 के तहत एक अदालत प्राप्तकर्ता देश के नामित केंद्रीय प्राधिकरण (भारत में विधि एवं न्याय मंत्रालय) को अनुरोध पत्र भेजती है, जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राष्ट्रीय संप्रभुता व सुरक्षा की जांच के बाद दस्तावेज स्थानीय अदालत को अग्रसारित करता है, जबकि अभिसमय का अनुच्छेद 19 घरेलू कानून की अनुमति होने पर विदेशी अदालत के क्लर्क को सीधे संबंधित स्थानीय अदालत को समन भेजने का विकल्प देता है। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 29(c) जिसे जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों पर लागू किया गया था और आदेश V के नियम 21 व 23 के तहत भारतीय अदालत अधिसूचित विदेशी सिविल कोर्ट से आए समन की तामील कराकर मूल अदालत को प्रमाणपत्र वापस भेजती है, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय अदालतें विदेश में समन भेजने या साक्ष्य जुटाने के लिए संहिता की धारा 77 व 78 तथा आदेश V के नियम 25 व 26 के अंतर्गत विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के माध्यम से 'लेटर्स रोगेटरी' भेजती हैं। जब अमेरिकी अदालत से स्वीकृत समन पैकेट दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेगा, तो प्राप्तकर्ता भारतीय न्यायाधीश उस समन की तामील कराने के लिए स्वत: बाध्य नहीं होंगे। चूंकि अमेरिकी कोर्ट क्लर्क भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) को दरकिनार करते हुए सीधे हेग सेवा अभिसमय के अनुच्छेद 19 और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 29(c) के तहत दस्तावेज भेज रहा है, इसलिए दिल्ली की अदालत के पास चार प्रमुख प्रक्रियात्मक विकल्प उपलब्ध होंगे।

सबसे पहले, चूंकि भारत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय को एकमात्र केंद्रीय प्राधिकरण नामित किया है और विदेश मंत्रालय ने भी 10 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया है कि विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील केवल इसी मंत्रालय के माध्यम से हो सकती है, इसलिए दिल्ली के जिला न्यायाधीश केंद्रीय प्राधिकरण को दरकिनार किए जाने या प्रतिवादियों के वास्तविक निवास स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारिता (आदेश V, नियम 21 सीपीसी) न होने के आधार पर पैकेट को प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार कर लौटा सकते हैं। दूसरे विकल्प के रूप में, विदेशी अदालत के अनुरोध को सीधे खारिज करने के बजाय दिल्ली की अदालत पैकेट को रिकॉर्ड पर लेकर विधि एवं न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को संदर्भित कर सकती है, ताकि भारत सरकार की यह औपचारिक राय ली जा सके कि इस समन की तामील से हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 के तहत राष्ट्रीय संप्रभुता या सुरक्षा प्रभावित होती है या नहीं। इसके विपरीत, तीसरे विकल्प के तहत यदि दिल्ली के न्यायाधीश जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना के साथ पठित सीपीसी की धारा 29(ठ) की अमेरिकी अदालत वाली व्याख्या को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे इस समन को भारतीय अदालत द्वारा जारी समन की तरह मानेंगे और आदेश ङ्क के नियम 21 व 23 के अंतर्गत स्थानीय प्रोसेस सर्वर या पंजीकृत डाक से तामील कराने का प्रयास कर तामील या अतामीली का प्रमाणपत्र न्यूयॉर्क अदालत को वापस भेजेंगे। अंतत:, चौथे विकल्प के रूप में दिल्ली की जिला अदालत अमेरिकी अदालत को एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के माध्यम से औपचारिक स्पष्टीकरण या आपत्ति भेज सकती है, क्योंकि स्वयं अमेरिकी न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने अपने 9 नवंबर 2026 के आदेश में यह गुंजाइश खुली रखी है कि यदि भारतीय प्राधिकरण या अदालतें भारतीय प्रक्रियात्मक कानून पर कोई औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत करती हैं, तो वे अपने आदेश की समीक्षा कर सकती हैं। कुल मिलाकर, न्यूयॉर्क अदालत का यह आदेश किसी अपराध या दोष का निर्धारण नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दीवानी प्रक्रिया के एक दुर्लभ और विवादास्पद प्रावधान का परीक्षण मात्र है। भारत के केंद्रीय प्राधिकरण संबंधी स्पष्ट रुख, दिल्ली की जिला अदालतों के न्यायिक विवेकाधिकार और अमेरिकी कानून के तहत संप्रभु व पदीय कृत्यों की उन्मुक्ति के मजबूत सुरक्षा कवच को देखते हुए, किसी भी विदेशी अदालत के लिए प्रक्रियात्मक पैंतरेबाज़ी के सहारे दूसरे संप्रभु राष्ट्र के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों पर बाध्यकारी क्षेत्राधिकार थोपना आसान नहीं होगा।

विचार

लोकसभाः परिसीमन और चुनौतियां

प्रो.डॉ.अरविंद नाथ तिवारी

भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां संसद की संरचना में बड़े बदलाव की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज होने वाली है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की अटकलें तेज हैं। यदि लोकसभा की वर्तमान 543 निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 हो जाती हैं तो देश की राजनीतिक व्यवस्था, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, चुनावी गणित और सरकारी खर्च पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती है। महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त भागीदारी दिलाना निश्चित रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। क्या भाजपा को मिलेगा राजनीतिक लाभ: भारतीय राजनीति में किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव का राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यदि लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर अधिकतम 850 तक पहुंचती है, तो चुनावी क्षेत्रों का स्वरूप बदल जायेगा। नये निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे और कई मौजूदा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव होगा। इसका सीधा प्रभाव राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। हालांकि, यह मान लेना कि सीटें बढ़ने का सीधा लाभ केवल भाजपा को मिलेगा, राजनीतिक वास्तविकताओं को सरल बनाकर देखना होगा। नये क्षेत्रों में विपक्षी दलों की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।दक्षिण भारत को लेकर भी राजनीतिक बहस महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा की राजनीतिक स्थिति उत्तर भारत जैसी मजबूत नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नये परिसीमन से उत्तर भारत का राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा और भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए दक्षिण भारत पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी?

850 सांसद और आर्थिक बोझ:आज देश की लोकसभा में 543 निर्वाचित सीट है, यदि यह संख्या बढ़कर 850 हो जाती है तो सांसदों की संख्या में लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके साथ ही संसद के संचालन पर होने वाला खर्च भी बढ़ेगा। एक सांसद को केवल वेतन देना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सांसदों को कार्यालय, आवास, यात्रा भत्ता, संसदीय क्षेत्र में कामकाज के लिए सुविधाएं, कर्मचारी, संचार व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। संसद के सत्र के दौरान सुरक्षा, परिवहन, भोजन, तकनीकी व्यवस्था और संसदीय सचिवालय पर भी खर्च होता है,यदि सांसदों की संख्या में इतनी बड़ी वृद्धि होती है तो इन सभी मदों में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। लोकसभा के साथ राज्यसभा की व्यवस्था और राज्य विधानसभाओं में भी सदस्यों की संख्या तथा आरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। राज्यों में विधानसभा सीटें बढ़ती हैं तो वहां भी भवन, कार्यालय, कर्मचारी, सुरक्षा और प्रशासनिक खर्च बढ़ने की संभावना है।सवाल यह है कि क्या देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति इस अतिरिक्त खर्च को आसानी से वहन कर सकती है? भारत जैसे विकासशील देश में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल और ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। यदि सरकार संसद और विधानसभाओं के विस्तार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करती है, तो यह भी देखना होगा कि उस खर्च से आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ मिलेगा। लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ने का एक सकारात्मक पक्ष भी है। वर्तमान में कई सांसदों को लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े होने के कारण सांसदों के लिए प्रत्येक गांव, पंचायत और शहरी क्षेत्र की समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना कठिन होता है,जो सहज हो जायेगा। महिलाओं का आरक्षण या राजनीतिक समीकरण: महिला आरक्षण का विषय किसी एक राजनीतिक दल के लाभ-हानि से ऊपर होना चाहिए। देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी मिलनी ही चाहिए। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी ने यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं नेतृत्व की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती हैं। यदि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है तो सरकार को इसके लिए स्पष्ट समय सीमा, पारदर्शी प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि आरक्षित सीटों का निर्धारण सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर हो।परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार बनाने से उन राज्यों के सामने भी सवाल खड़े होंगे जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों की चिंता यही रही है कि जनसंख्या वृद्धि को ही प्रतिनिधित्व का एकमात्र आधार बनाने से उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है।

एक नजर

रामनगर अंचल कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जाँच की माँग, राज्यपाल को भेजा पत्र

सद्भावना टुडे

रामनगर (पश्चिम चम्पारण)। पश्चिम चम्पारण जिले के रामनगर अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों पर लोक जागरण मंच ने गंभीर रुख अपनाया है। मंच के महामंत्री सईद सिद्दीकी ने महामहिम राज्यपाल, बिहार को विस्तृत पत्र भेजकर रामनगर अंचल अधिकारी एवं संबंधित राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जाँच कराने की माँग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि अवैध निर्माण के नाम पर आम नागरिकों को नोटिस जारी करने तथा राजस्व संबंधी रिपोर्ट तैयार करने और मामलों के निपटारे के नाम पर कथित रूप से पैसों की माँग की जाती है। कुछ शिकायतों में दो लाख रुपये तक की कथित रिश्वत माँगे जाने की बात सामने आई है। इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच कराने की माँग की गई है। सईद सिद्दीकी ने सवाल उठाया है कि यदि रामनगर में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, तो अंचल अधिकारी के कार्यकाल में नगर के बीचोंबीच सैकड़ों निर्माण कैसे हो गए? सरकारी जमीन पर कब्जे और विवादित भूमि पर निर्माण के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सभी मामलों की प्रशासनिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोक जागरण मंच ने राज्यपाल से अंचल कार्यालय के नोटिस रजिस्टर, राजस्व रिपोर्ट, भूमि संबंधी आदेशों, वित्तीय लेन-देन तथा संबंधित अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति की वैधानिक जाँच कराने की माँग की है। साथ ही कथित अवैध वसूली में बिचौलियों और भू-माफियाओं की भूमिका की भी जाँच कराने का अनुरोध किया है। सईद सिद्दीकी ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अभियान नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है। किसी को भी बिना निष्पक्ष जाँच दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन गंभीर शिकायतों को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि रामनगर की जनता को विवाद नहीं, विकास चाहिए; राजनीति नहीं, पारदर्शिता चाहिए और प्रशासनिक दबदबा नहीं, सम्मान एवं न्याय चाहिए। लोक जागरण मंच ने स्पष्ट किया है कि यदि शिकायत पर प्रशासन गंभीरता से संज्ञान लेकर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है, तो मंच आम जनता को जागरूक करते हुए चरणबद्ध शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक जनआंदोलन शुरू करेगा। मंच ने रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, युवाओं और आम नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की अपील की है। लोक जागरण मंच का संकल्प है—जनहित, जनभागीदारी और जनजागरण।

उदीयमान सूर्य को अर्ध्य के साथ ही लोक आस्था का महापर्व सम्पन्न

अररिया। चार दिनों से चली आ रही लोक आस्था का महापर्व छठ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के साथ संपन्न हुआ।अहले सुबह से ही जिले के विभिन्न नदियों,तालाबों और पोखरों पर बने घाट पर छठव्रती और श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गया था। सूर्योदय से पहले छठव्रती पानी में जाकर भगवान भास्कर की आराधना करते हुए छठी माई की पूजा अर्चना हाथ में फल फूल और अन्य पूजन सामग्री के साथ सूप लेकर की।मौसम के बदले रुख के बीच छठव्रती पानी में डुबकी लगाते हुए भगवान भास्कर की आराधना करते हुए सुख समृद्धि और स्वस्थ लंबी आयु की कामना की। विभिन्न घाटों पर छठ पूजा समिति की ओर से अर्घ्य के लिए गाय के दूध की व्यवस्था की गई थी,जिसे छठव्रतियों और श्रद्धालुओं के बीच मुफ्त वितरित किया गया।छठ को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के साथ विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और बलों की प्रतिनियुक्ति की गई,जो भीड़ को नियंत्रित करने के साथ छठव्रतियों को घाट तक पहुंचाने की कवायद करते देखे गए। अररिया के परमान नदी के त्रिशूलिया घाट,बकरा नदी के तट पर,नहर के साथ ही विभिन्न तालाबों और पोखरों में घाट का निर्माण किया गया था।अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए रातभर घाट पर चहल पहल रही।अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद रात में गन्ने का छत्रप के साथ छठव्रतियों ने कोशी भराई की रस्म की अदायगी भी की।श्रद्धाभाव के साथ कोशी का विसर्जन घाट पर किया गया।इस दौरान छठव्रतियों के साथ महिलाएं छठ की लोक पारंपरिक गीतों का गायन रातभर करती रही। फारबिसगंज के कोठीहाट नहर,सुल्तान पोखर,कॉलेज चौक शायरानगर नहर, डॉ अलख बाबू का पोखर,श्री पंचमुखी हनुमान सरोवर,सीताधार सहित अन्य पोखरों और तालाबों,जोगबनी में परमान नदी के तट,नगर परिषद के कार्यालय के पास के सरोवर के पास बने घाटों पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया गया।छठव्रतियों ने सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया,वहीं छठव्रतियों के पैर छूने की होड़ भी श्रद्धालुओं में देखी गई।घाट पर बच्चों के द्वारा जमकर पटाखे और आतिशबाजी भी की गई।वही जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन की ओर से छठ को लेकर घाट सहित शहर और आने जाने वाले रास्तों में रोशनी की समुचित व्यवस्था की गई थी।कुल मिलाकर जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।

भागलपुर से आनंद विहार, पटना और जयपुर सहित कई मार्गों पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू

भागलपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ के समापन के साथ ही परदेश और अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ भागलपुर रेलवे जंक्शन पर उमड़ने लगी है। नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे प्रशासन ने भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली), पटना, जयपुर और साहिबगंज सहित अन्य प्रमुख मार्गों के लिए अनारक्षित और आरक्षित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए आनंद विहार टर्मिनल (गाड़ी संख्या 04061/04062) के बीच 26 नवंबर तक विशेष ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जो शाम 4:30 बजे भागलपुर से प्रस्थान करती है। इसके अलावा, दिल्ली रूट पर यात्रियों की तत्काल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भागलपुर से आनंद विहार के बीच वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जिससे बिना आरक्षण वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिल रही है। सोमवार 16 नवंबर से अंग एक्सप्रेस के रैक से भागलपुर-पटना स्पेशल ट्रेन (03431) का परिचालन शुरू किया गया है, जो सुबह 11:10 बजे रवाना होकर सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर के रास्ते पटना जाएगी। इसके अतिरिक्त, 18 नवंबर को भागलपुर से जयपुर के लिए भी विशेष गाड़ी चलाई जाएगी। स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर और साहिबगंज के बीच (03453/03454) 20 नवंबर तक प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन का परिचालन जारी है। छठ के बाद स्टेशन पर 20 से 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण कर सुरक्षा व यात्री सुविधाओं की समीक्षा की है।

भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष अश्विनी जोशी 'मोन्टी' लोजपा (रामविलास) में शामिल

भागलपुर। जिले की स्थानीय राजनीति में सोमवार को एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और भागलपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अश्विनी जोशी 'मोन्टी' ने भाजपा का दामन छोड़कर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह के दौरान लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने उन्हें अपने समर्थकों के साथ विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। मिलन समारोह के दौरान खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान, विधायक बाबूलाल शौर्य, नाथनगर के विधायक मिथुन यादव और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता यामिनी मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सभी नेताओं ने मोन्टी के पार्टी में आने का स्वागत किया और इसे भागलपुर क्षेत्र में संगठन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अश्विनी जोशी 'मोन्टी' ने कहा कि वे चिराग पासवान के 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के विजन से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लोजपा (रामविलास) के माध्यम से एनडीए को और अधिक मजबूत करने और संगठन को नई ऊंचाई देने के लिए काम करेंगे। अश्विनी जोशी 'मोन्टी' का पार्टी छोड़ना भागलपुर नगर और जिला भाजपा के लिए सांगठनिक दृष्टिकोण से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वे वर्तमान में भागलपुर



नगर निगम के वार्ड संख्या-38 से पार्षद और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हैं। इससे पहले वे भाजपा के जिला प्रवक्ता और जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला महामंत्री और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भी रह चुके हैं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारिता की चुनौतियों और जिम्मेदारियों पर हुआ मंथन

सुपौल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सोमवार, 16 नवंबर को जिला प्रशासन, सुपौल के तत्वावधान में प्रेस क्लब में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप, बदलती चुनौतियों और समाज के प्रति मीडिया की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम (पत्रकारिता: लोकलुभावन या जिम्मेदार) रखी गई थी। इस विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक शरथ आर.एस. सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संजय कुमार सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े कई पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता की बदलती भूमिका और वर्तमान दौर में मीडिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर गंभीर विमर्श हुआ। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता केवल समाचारों के प्रकाशन और प्रसारण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने, जनसमस्याओं को सामने लाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण आधार भी है। पत्रकारों पर समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए समाचारों के संकलन, सत्यापन और प्रसारण के दौरान निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चर्चा के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि आज के दौर में खबरों की तेजी के साथ उनकी विश्वसनीयता बनाए रखना बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के विस्तार से सूचनाओं का प्रसार काफी तेज हुआ है। ऐसे में किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी है। बिना पुष्टि के खबरों का प्रसारण समाज में भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकता है। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य तथ्यों के आधार पर जनता तक सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना होना चाहिए। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देना, सामाजिक सरोकारों को सामने लाना और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों एवं मूल्यों को बनाए रखना प्रत्येक पत्रकार का दायित्व है।

अमित भगत हत्याकांड में एसआईटी ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार, एक विधि विरुद्ध बालक हिरासत में

अररिया। जिले के कुर्साकांटा के पहुंसी में शनिवार को दिनदहाड़े हुए मोहरिल अमित भगत हत्याकांड मामले में एसपी जितेन्द्र कुमार द्वारा गठित एसआईटी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।वहीं एक विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।इस बात की पुष्टि एसपी जितेन्द्र कुमार ने की। गिरफ्तार आरोपियों में कुआड़ी थाना के पहुंसी गांव के रहने वाले वृक्ष लाल सिंह पिता स्व.मोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह पिता सत्तन सिंह है।पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी,घटना के बाद भागने में उपयोग में लाया गया मोटरसाइकिल और दो खोखा बरामद किया है।

उल्लेखनीय हो कि 14 नवम्बर को सुबह साढ़े नौ बजे कुआड़ी थाना क्षेत्र के पहुंसी में अमृत कुमार भगत उर्फ अमित भगत, पिता बद्रीनाथ भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया था, जहां उपचार के दौरान चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी जितेन्द्र कुमार ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया।गठित एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे अवैध सम्बन्ध को लेकर विवाद होने की बात कह रही है। घटना के संबंध में कुआड़ी थाना कांड संख्या 108/26, दिनांक 14.11.2026, धारा 103(2),61(2)(ए),125(बी), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के अंतर्गत नौ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुआड़ी थाना पुलिस ने कांड के दो नामजद अभियुक्तों वृक्ष लाल सिंह एवं लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया है। मृतक के घर से निकलने की सूचना देने के आरोप में एक विधि-विरुद्ध बालक लाइनर को निरुद्ध किया गया है।अन्य अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु लगातार छापामारी एवं अनुसंधान जारी होने की बात एसपी ने कही।

भास्कर महोत्सव में सात वर्षीय कृतिका के नृत्य ने बटोरीं खूब तालियां, स्नेहा झा के लोकगीतों ने बांधा समां

सहरसा। शहर के मत्स्य विभाग स्थित सात पोखरिया घाट पर लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन सहरसा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय भास्कर महोत्सव सोमवार को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन कलाकारों की गीत-संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम के दौरान सात वर्षीय बाल कलाकार कृतिका झा मिष्टी अपनी शानदार नृत्य प्रस्तुति से आकर्षण का केंद्र बनी रही। पतरघट प्रखंड क्षेत्र के कहरा निवासी कृतिका के मंच पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा। वायरल गर्ल के नाम से चर्चित कृतिका ने 'पटना के घाट पर...', 'केलवा के पात पर...' सहित अन्य लोकप्रिय छठ गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। वहीं, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा झा ने अपनी सुरीली आवाज में 'शीतली बयरिया...', 'समा खेले चलली...' सहित विभिन्न लोकगीतों की प्रस्तुति देकर महोत्सव में लोक संस्कृति का रंग घोल दिया। उनकी गायिकी पर दर्शक झूमते नजर आए। महोत्सव में स्थानीय गायक वेद प्रकाश, शास्त्रीय संगीत गायिका त्रिशा आनंद, शास्त्रीय नृत्यांगना जिम्मी शर्मा, लोकगीत गायिका निगम कुमारी एवं डॉली कुमारी की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। सभी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को यादगार बनाया। मालूम हो कि कृतिका झा मिष्टी महज



चार वर्ष की उम्र से ही सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। वह सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के कई प्रमुख महोत्सवों में प्रस्तुति देकर बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। जिला स्थापना दिवस, वसंत महोत्सव, कोसी महोत्सव, उग्रतारा महोत्सव, मकर संक्रांति महोत्सव, सुपौल के तिलहेश्वर महोत्सव तथा मधेपुरा के सिंहेश्वर महोत्सव में भी वह अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। बेहतर प्रदर्शन के लिए सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला प्रशासन की ओर से कृतिका को कई बार प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा चुका है। वसंत महोत्सव में उसकी नृत्य प्रस्तुति के वीडियो को ढाई लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। वर्तमान में वह स्वरांजलि में प्रो. भारती सिंह के मार्गदर्शन में गायन तथा आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान में नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने साथ समापन

पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर पटना से लेकर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गयाजी और दरभंगा तक छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चार दिवसीय इस महाअनुष्ठान के चौथे दिन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हो गया। आज चौथे दिन उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। राजधानी पटना समेत तमाम छठ घाटों पर लाखों की संख्या में छठ व्रतियों ने छठ पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह जिले मुंगेर के तारापुर स्थित पैतृक गांव लखनपुर में सोमवार सुबह परिवार के साथ पारंपरिक विधि-विधान से उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर राज्य की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री रविवार देर रात पटना से सड़क मार्ग के जरिए लखनपुर पहुंचे थे। गांव के लोगों में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने अपने परिजनों के साथ लखनपुर उत्तर टोला स्थित छठ घाट पर पहुंचकर व्रतियों के साथ मिलकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। महापर्व की इस पावन बेला पर पूरा वातावरण छठ के पारंपरिक गीतों और भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने घाट पर मौजूद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का अभिवादन भी स्वीकार किया और सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद मुख्यमंत्री



सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र के रणगांव में करीब सभी छठ घाटों का भ्रमण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपने पटना स्थित आवास पर छठ पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान भास्कर और छठी मैया को नमन करता हूं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए हैं, जिसमें कठोर अनुशासन और शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं। मैं अपने देश और बिहार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि छठी मैया की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ताकि हम हर साल इसी ऊर्जा और शक्ति के साथ इस महान पर्व को मना सकें। उन्होंने कहा कि आज बिहार से जो संदेश स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता और अनुशासन का संदेश निकल रहा है, वह पूरे देश और दुनिया तक पहुंच रहा है। बिहार का यह महान पर्व दुनिया के सामने राज्य की परंपराओं और संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। छठी मैया की जय हो; बिहार की संस्कृति की जय हो।

प्रकृति और संस्कृति के महापर्व छठ का हुआ समापन, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ समाप्त हुआ 4 दिवसीय अनुष्ठान

सहरसा। प्रकृति और संस्कृति का महापर्व छठ सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हो गया। चार दिनों तक चले इस कठिन अनुष्ठान में व्रतियों ने निर्जला रहकर भगवान भास्कर की आराधना की। घाटों पर कम पड़ रही जगहों के कारण लोग घर की छतों पर भी घाट बनाकर छठ मनाना शुरू कर दिया है। शहर के 103 और जिले के सभी 10 प्रखंडों में घोषित 38 घाटों पर छठ पर्व संपन्न हुई। साथ ही मन्नत पूरी होने पर छठ में अचरी नाच, दंड प्रणाम की परंपरा को श्रद्धालु निभाते आ रहे हैं।

रविवार की शाम व्रती अपने परिवार सहित घाट पर पहुंचे। शाम 5 बजे सूर्यास्त के समय व्रतियों ने सूप में फल-फूल, ठेकुआ और प्रसाद सजाकर डूबते सूर्य को 4.54 बजे के बाद से पहला अर्घ्य दिया जाना शुरू हुआ। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छठ के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। सोमवार की सुबह व्रती एक बार फिर घाटों पर पहुंचे। सुबह 6.02 बजे सूर्योदय होते ही व्रतियों ने डुबकी लगाकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना प्रारंभ किया। और अपने व्रत का पारण किया। इसके बाद सभी ने एक-दूसरे को प्रसाद बांटा और सुख-समृद्धि की कामना की। नहाय-खाय से शुरू हुए इस पर्व में खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा का विधिवत पालन किया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से घाटों



पर सफाई, सुरक्षा और प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई थी। छठ के समापन के साथ ही लोगों में दीपावली के बाद की सबसे बड़ी आस्था का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। प्रकृति और संस्कृति का महापर्व छठ के बारे में पर्यावरणविद भगवानजी पाठक ने कहा की इस पर्व में किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि सीधे सूर्य, जल, नदी, तालाब और प्रकृति की पूजा होती है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। संस्कृति का पर्व इसलिए कि इसमें जात-पात, अमीर-गरीब का कोई भेद नहीं रहा है। घाट पर सभी एक साथ खड़े होते हैं। ठेकुआ, खरना, नहाय-खाय सब सदियों पुरानी परंपरा है।

एक नजर

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी : अंडर-19 एशिया कप के हीरो मोहित उल्वा सौराष्ट्र टीम से जुड़े



नई दिल्ली। ओमान में खेले गए पुरुष अंडर-19 एशिया कप के रोमांचक फाइनल में भारत को खिताब दिलाने वाले तेज गेंदबाज ऑलराउंडर मोहित उल्वा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सौराष्ट्र की सीनियर टीम से जुड़ गए हैं। भारत की खिताबी जीत के महज दो दिन बाद उन्हें सौराष्ट्र की टीम में शामिल किया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी। संघ ने बताया कि मोहित उल्वा इंदौर में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लीग मुकाबलों के लिए टीम से जुड़ गए हैं। संघ की ओर से साझा की गई तस्वीर में मोहित कप्तान जयदेव उनादकट, मुख्य कोच नीरज ओडेदरा और कोच शेल्डन जैक्सन के साथ नजर आए। हालांकि, इंदौर के डेली कॉलेज मैदान पर हरियाणा के खिलाफ जारी सौराष्ट्र के मुकाबले की अंतिम एकादश में मोहित को जगह नहीं मिली। सौराष्ट्र के एलीट ग्रुप बी में अभी कुछ और मुकाबले बाकी हैं, ऐसे में उन्हें आगे मौका मिलने और सीनियर टीम के लिए टी20 पदार्पण करने की उम्मीद है। मोहित ने शनिवार को ओमान के अल अमेरात स्थित मिनिस्ट्री टर्फ ग्राउंड-2 पर पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में यादगार प्रदर्शन किया था। भारत को खिताब जीतने के लिए 338 रन बनाने थे और टीम 252 रन पर आठ विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। ऐसे समय में दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 188 से अधिक रहा।

भारत को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे। मोहित ने मिड-ऑफ के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाकर चौका जड़ दिया और भारत को शानदार जीत दिला दी। उनके इस शॉट के बाद मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। मोहित ने मनाल चौहान के साथ नौवें विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी की। इसके बाद आखिरी बल्लेबाज चिगुरुपति वेंकट के साथ 16 गेंदों में नाबाद 30 रन जोड़कर भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया। मुख्य रूप से तेज गेंदबाज मोहित ने फाइनल में भारत की ओर से नई गेंद से गेंदबाजी भी की थी। हालांकि, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और उन्होंने आठ ओवर में 57 रन दिए। इस बीच, अंडर-19 एशिया कप के लीग चरण में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले अर्जुन राजपूत के भी घरेलू टी-20 टूर्नामेंट के लिए पंजाब टीम से जुड़ने की जानकारी मिली है। सौराष्ट्र की तरह पंजाब को भी एलीट ग्रुप बी में रखा गया है। पंजाब 2023-24 सत्र में इस प्रतियोगिता का चैंपियन रहा था।

सचिन तेंदुलकर ने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के साथ खेला गली क्रिकेट



मुंबई। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने सोमवार सुबह ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट के साथ मुंबई में गली क्रिकेट खेला। बल्लार्ड एस्टेट में आयोजित इस खास सत्र के दौरान वहां मौजूद स्कूली बच्चों ने तीनों का उत्साह बढ़ाया और क्रिकेट का आनंद लिया। सचिन ने सड़क पर बल्ले और गेंद दोनों से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रिंस विलियम के खिलाफ बल्लेबाजी की और बाद में प्रिंसेस केट को गेंदबाजी भी की। इस दौरान विलियम और केट ने भी बल्ला थामकर क्रिकेट खेला। वहां मौजूद बच्चों को भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का मौका मिला। बच्चों ने अतिथियों के सामने अपना खेल दिखाने की कोशिश की। क्रिकेट सत्र से पहले सचिन ने प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के साथ कुल्हड़ वाली चाय का आनंद भी लिया। तीनों को पास की एक दुकान से कुल्हड़ में चाय पीते हुए देखा गया। ब्रिटेन का शाही दंपती तीन दिवसीय भारत दौरे पर है। वे मुंबई में छठे वार्षिक अर्थशॉट पुरस्कार समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। मंगलवार को पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने के बाद दोनों नई दिल्ली जाएंगे। यहां बुधवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है। विलियम और केट की यह दूसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। इससे पहले दोनों अप्रैल 2016 में भारत आए थे। सचिन हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) 2026 की नीलामी में भी शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने युवा खिलाड़ियों को तकनीक का इस्तेमाल अभ्यास में मददगार के रूप में करने की सलाह दी थी, न कि उसे ध्यान भटकाने का जरिया बनाने की। सचिन ने कहा था, 'तकनीक मददगार होनी चाहिए, ध्यान भटकाने वाली नहीं। अभ्यास के दौरान इसका इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप मुकाबले के लिए मैदान पर उतरें तो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर भरोसा करें और अपने अवचेतन मन को काम करने दें।' 16 नवंबर की तारीख सचिन के क्रिकेट करियर के लिहाज से भी खास है। इसी दिन वर्ष 2013 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। दो दशक से अधिक लंबे करियर में सचिन ने 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 34,357 रन बनाए। उनके नाम 100 शतक और 164 अर्धशतक दर्ज हैं। भारतीय जर्सी में उनका आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में था। इस मैच में उन्होंने 74 रन की शानदार पारी खेलकर अपने यादगार अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन किया। सचिन को क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है।

जय शाह लगातार दूसरी बार निर्विरोध आईसीसी अध्यक्ष नियुक्त, बोर्ड ने जताया भरोसा



नई दिल्ली,एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने जय शाह को लगातार दूसरी बार अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाली में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठकों के दौरान निदेशकों के प्रस्ताव के बाद शाह को निर्विरोध दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। इस फैसले से वैश्विक क्रिकेट के नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी। आईसीसी बोर्ड का यह निर्णय शाह के नेतृत्व में उसके भरोसे को दर्शाता है। क्रिकेट के वैश्विक विस्तार, प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने और व्यावसायिक विकास के लिहाज से यह खेल के लिए महत्वपूर्ण दौर है। क्रिकेट लॉस एंजिलिस ओलंपिक-2028 में वापसी की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही आईसीसी ने प्रतियोगिताओं के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम का विस्तार भी घोषित किया है, जिससे अधिक खिलाड़ियों को भागीदारी और विकास के अवसर मिल सकेंगे।

बोर्ड ने क्रिकेट की बुनियाद मजबूत करने, महिला क्रिकेट के विकास को समर्थन देने, एसोसिएट सदस्यों के लिए अवसर बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की विश्वसनीयता बनाए रखने और खेल के दीर्घकालिक भविष्य के लिए टिकाऊ व्यावसायिक अवसर विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त होने पर जय शाह ने आईसीसी के हवाले से कहा, 'आईसीसी बोर्ड ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सभी निदेशकों के निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आईसीसी अध्यक्ष के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं दुनिया भर में क्रिकेट के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने कहा, 'हम अपने खेल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। लॉस एंजिलिस ओलंपिक-2028 में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने और खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने का असाधारण अवसर है। शाह ने कहा, 'हमारी जिम्मेदारी केवल सफल प्रतियोगिताओं के आयोजन तक सीमित नहीं है। हमें प्रशंसकों, खिलाड़ियों, व्यावसायिक साझेदारों और अन्य प्रमुख हितधारकों को ध्यान में रखते हुए खेल के लिए अधिक मजबूत और टिकाऊ भविष्य तैयार करना होगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लोगों को एकजुट करने की क्षमता ही क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है। बोर्ड और अपने सदस्यों के समर्थन से हमारा ध्यान अपनी महत्वाकांक्षाओं को ठोस कदमों में बदलने और ऐसी प्रगति सुनिश्चित करने पर होगा, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले।' इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने शाह की पुनर्नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा, 'जय का नेतृत्व ऐसे समय में जारी रहेगा, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। खेल तेजी से बदल रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को मजबूत करें, द्विपक्षीय क्रिकेट की प्रासंगिकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखें तथा बड़ी प्रतियोगिताओं को खेल के भविष्य के केंद्र में रखें। उन्होंने कहा, 'आने वाले वर्षों में क्रिकेट की परंपराओं और नवाचार, नए दर्शकों तथा बदलते व्यावसायिक परिदृश्य से मिलने वाले अवसरों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: रजत पाटीदार के तूफानी शतक की बदौलत मध्य प्रदेश की 131 रन से जीत

नई दिल्ली। रजत पाटीदार की 48 गेंदों में नाबाद 135 रन की तूफानी पारी की बदौलत मध्य प्रदेश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में सोमवार को असम को 131 रन से करारी शिकस्त दी। दिन के अन्य मुकाबलों में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने भी जीत दर्ज की। न्यू चंडीगढ़ के पीसीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मध्य प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 250 रन बनाए। पाटीदार ने अपनी विस्फोटक पारी में विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्हें शिवांग कुमार का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 38 गेंदों में 61 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी कर मध्य प्रदेश को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अंकुश सिंह ने 13 गेंदों में 23 और अक्षत रघुवंशी ने 11 गेंदों में 19 रन का योगदान दिया। असम की ओर से आकाश सेनगुप्ता ने तीन और मृण्मय दत्ता ने दो विकेट लिए।

जवाब में असम की टीम 17.4 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। सिबशंकर रॉय ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि साहिल जैन ने 20 और प्रद्युम्न सैकिया ने 18 रन का योगदान दिया। मध्य प्रदेश की ओर से कुमार कार्तिकेय ने 17 रन देकर तीन विकेट लिए। आवेश खान और राहुल बाथम ने दो-दो विकेट हासिल किए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को छह रन से शिकस्त दी। जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 201 रन बनाए। कमरान इकबाल ने 37 गेंदों में 70 और शुभम खजूरिया ने 34 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। अब्दुल समद ने 14 गेंदों में 29 रन बनाकर टीम को तेज गति प्रदान की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की टीम ने जोरदार संघर्ष किया। अमित सात्विक ने 31 गेंदों में 67 रन बनाए। नारायण जगदीशन ने 35 और आर. राजकुमार ने महज 10 गेंदों में 24 रन का योगदान दिया। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने अहम मौकों पर विकेट लेकर तमिलनाडु को नौ विकेट पर 195 रन तक ही रोक दिया। लोन नासिर मुजफ्फर ने तीन विकेट लिए, जबकि सुनील कुमार और बृजेश शर्मा को दो-दो सफलताएं मिलीं। कमरान इकबाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उत्तराखंड ने गोवा को पांच विकेट से हराया। गोवा की टीम 19.4 ओवर में 168 रन पर ऑलआउट हो गई।

70वीं राष्ट्रीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची केरल और तमिलनाडु की टीमें

नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में चल रही 70वीं राष्ट्रीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता 2026-27 आयु वर्ग 19 वर्ष बालक में सोमवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए केरल और तमिलनाडु की टीमों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। केरल ने दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर को तथा तमिलनाडु ने पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश को 6-6 विकेट से पराजित किया।

अब मंगलवार, 17 नवंबर को खिताबी मुकाबले में केरल और तमिलनाडु के बीच भिड़ंत होगी, जबकि तीसरे स्थान के लिए जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश की टीमें आमने-सामने होंगी। प्रतियोगिता में सोमवार को रुद्र मैदान में आयोजित सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं एवं आयोजन को भी देखा। मंत्री सिंह एवं अन्य अतिथियों का जिला क्रीड़ा अधिकारी तथा आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोहानी के स्टेडियम मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में केरल ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी जम्मू-कश्मीर की टीम 19.2 ओवर में 135 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से करनवीर शर्मा ने 30 गेंदों में 53 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। अथीर रफीक ने 9 गेंदों में 16 तथा काशिफ ने 20 गेंदों में 13 रन बनाए। केरल की ओर से नभय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए, जबकि अनाह और धनुष ने 2-2 विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर की टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केरल की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की। आश्मित ने 22 गेंदों में 37 रन, क्रिस ने 16 गेंदों में 24 रन तथा जतिन ने 13 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया। केरल ने 6 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर फाइनल में जगह बनाई। मैच के शुभारंभ से पहले मैदान की परंपरा के अनुसार अतिथियों एवं खिलाड़ियों का बैंड दल के साथ प्रभारी अजय शर्मा एवं स्टॉफ द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया।

'डिप्लोमैटिक क्रिकेट कप' के फाइनल में 'ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन टाइगर्स' ने 'ब्रिटिश हाई कमीशन लायंस' को दी मात

धर्मशाला,एजेंसी। ब्रिटिश उच्चायोग और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने 14-15 नवंबर को धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में पहले 'डिप्लोमैटिक क्रिकेट कप' का संयुक्त रूप से आयोजन किया। टूर्नामेंट के पहले संस्करण में तीन टीमों ने हिस्सा लिया जिनमें 'ब्रिटिश हाई कमीशन लायंस', 'ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन टाइगर्स' और 'दिल्ली एक्सपैट्स क्रिकेट क्लब' शामिल रहे। टूर्नामेंट का समापन एक रोमांचक फाइनल के साथ हुआ, जिसमें 'ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन टाइगर्स' ने 'ब्रिटिश हाई कमीशन लायंस' को हराकर पहली ट्रॉफी अपने नाम की।

टूर्नामेंट का एक खास आकर्षण एक प्रदर्शनी मैच (एग्जीबिशन मैच) रहा, जिसमें तीनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। इस टीम का मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की टीम से हुआ। चंडीगढ़ में ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त, अल्बा स्मेरिग्लियो ने उद्घाटन और समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सभी टीमों का हौसला बढ़ाया और इस आयोजन की खेल भावना की सराहना की। टूर्नामेंट से पहले, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने स्टेडियम में सभी टीमों से मुलाकात की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पहले 'डिप्लोमैटिक क्रिकेट कप' ने यह दिखाया कि क्रिकेट समुदायों और देशों के बीच एक पुल का काम करता है। ब्रिटिश उच्चायोग और एचपीसीए के इस सहयोग ने लोगों के बीच



आपसी संबंधों को मजबूत करने, खेल के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और भारत, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के प्रति साझा जुनून का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान किया। ब्रिटिश उच्चायोग ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के आयोजन के लिए एचपीसीए के सहयोग और मेहमाननवाजी का आभार जताया, जिससे यह पहला संस्करण एक यादगार खेल आयोजन बन गया। एचपीसीए ने भी 'ब्रिटिश हाई कमीशन', 'ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन' और 'दिल्ली एक्सपैट्स क्रिकेट क्लब' को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की मेजबानी करने की उम्मीद जताई।

तीसरे दिन फुटबॉल के 11 मुकाबलों में दिखा रोमांच, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की बड़ी जीत

कानपुर,एजेंसी। सेंट्रल जोन अंतर-विश्वविद्यालयीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। तीसरे दिन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने 8-0 और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने 7-0 से बड़ी जीत दर्ज की, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ विश्वविद्यालय को 5-3 से हराया। यह बातें रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में प्रतियोगिता के तीसरे दिन के मुकाबलों के संपन्न होने पर सचिव खेल एवं आयोजन सचिव शुभम हजारिया ने कहीं।

सीएसजेएमयू में आयोजित प्रतियोगिता के तीसरे दिन निर्धारित सभी 11 मुकाबले संपन्न हुए। इनमें 10 मैच मैदान पर खेले गए, जबकि एक मुकाबले में वॉकओवर दिया गया। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ग्वालियर को 4-0 से हराया। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को 3-0 से शिकस्त दी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ की टीम के निर्धारित समय पर मैदान में नहीं पहुंचने पर मेडी-कैप्स विश्वविद्यालय को वॉकओवर मिला। शुआट्स प्रयागराज ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को 2-0 से हराया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने राजीव गांधी पी.



विश्वविद्यालय को 7-0 से पराजित किया। वहीं, आईआईटी कानपुर के मैदान पर गलगोटिया विश्वविद्यालय ने एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल को 7-0 से हराया।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 5-3 से जीत हासिल की। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय को 8-0 से हराया। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय को 3-0 से शिकस्त दी। दिन के अंतिम मुकाबले में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को 2-1 से पराजित किया। शुभम हजारिया ने कहा कि नॉकआउट प्रारूप में प्रत्येक मुकाबला महत्वपूर्ण होता है। खिलाड़ियों ने उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रदर्शन किया है। आयोजन व्यवस्था और सभी टीमों के बेहतर समन्वय से तीसरे दिन के सभी मुकाबले सफलतापूर्वक संपन्न हुए। प्रतियोगिता में शामिल सभी टीमों को बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहयोग करेगी : डॉ. मोहन यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। किसी भी खेल की अकादमी स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। प्रदेश में प्रत्येक खेल को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार शाम को इंदौर में भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ (बीएसएफआई) के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप-2026 के शुभारंभ समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ के 100 वर्ष पूरे होना ऐतिहासिक उपलब्धि का अवसर है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर महासंघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों तथा मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एवं स्नूकर संघ को उन्होंने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि तीन दिनों के भीतर प्रदेश में दो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इंदौर में आयोजित इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 35 देशों के 150 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सभी विदेशी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इंदौर मां अहिल्या की नगरी और मालवा की आर्थिक राजधानी है। यहां अतिथि सत्कार की समृद्ध परंपरा है। प्रदेश में आने वाले सभी खिलाड़ियों को बेहतर आतिथ्य और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 19 नवम्बर को मध्य प्रदेश में महिला हॉकी की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भी आयोजित होने जा रही है। यह प्रदेश में खेल गतिविधियों के विस्तार और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के बढ़ते अवसरों का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को मिल रहे प्रोत्साहन का जिक्र करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी खेलों को समान महत्व दिया जा रहा है।

ओलंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं। खेलों के प्रति सरकार की सकारात्मक नीतियों और खिलाड़ियों को मिल रहे अवसरों से नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खेल प्रशिक्षकों के भविष्य और सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित और उज्ज्वल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने खेल एवं खेल प्रशिक्षकों से संबंधित व्यवस्थाओं में आवश्यक संशोधन किए थे, ताकि खेल प्रशिक्षकों को भी उच्च शैक्षणिक पदों और पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षक केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे देश के भविष्य के खिलाड़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश में खेलों को शिक्षा व्यवस्था से भी जोड़ा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत खेलों को विषय के रूप में शामिल किए जाने से विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि और प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा।

एक नजर

जी-20 की अध्यक्षता को लेकर ब्रिटेन को रूस की चेतावनी, कहा- अधिकारों में दखल के होंगे गंभीर परिणाम

मॉस्को। रूस ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि वर्ष 2027 में जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद यदि उसने मॉस्को के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस की यह प्रतिक्रिया ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के उस कथित बयान के करीब दो सप्ताह बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध को लेकर ब्रिटेन के प्रतिबंधों के कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल नवंबर में मैनचेस्टर में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। रूस के विदेश मंत्रालय में जी-20 और एपेक मामलों के राजदूत मरात बर्दियेव ने सरकारी समाचार एजेंसी 'रिया नोवोस्ती' से कहा कि लंदन का वास्तविक रुख सामने आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस के अधिकारों का कोई भी उल्लंघन नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और इस दिशा में उठाए गए गलत कदमों के गंभीर परिणाम होंगे। बर्दियेव ने उम्मीद जताई कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जी-20 की अध्यक्षता करने वाले देश को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि संगठन की गतिविधियों में कौन भाग लेगा। उनके मुताबिक, अध्यक्ष देश मंच के कामकाज में शामिल होने वाले देशों पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता।

यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के अलग-थलग करने के प्रयासों के बावजूद रूस जी-20 का सदस्य बना हुआ है। परंपरा के अनुसार, मेजबान देश संगठन के सभी सदस्य देशों को वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण देता है। इस बीच, मौजूदा अध्यक्ष अमेरिका ने दिसंबर में मियामी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन को निमंत्रण दिया है। हालांकि, क्रेमलिन ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि रूसी राष्ट्रपति स्वयं सम्मेलन में शामिल होंगे या उनकी जगह कोई प्रतिनिधि भेजा जाएगा।

इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नेतृत्व से मिले ईरान के विदेश मंत्री अराघची

इस्लामाबाद। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात की। यह बैठक आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ) के मंत्रिपरिषद की 30वीं बैठक से इतर हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बताया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और ईरान के बीच मजबूत और भाईचारे वाले संबंधों की पुष्टि की। साथ ही उच्चस्तरीय संवाद जारी रखते हुए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अराघची ने सोमवार शाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के सामने मौजूद चुनौतियों तथा खतरों पर चर्चा हुई।

'देर होने से पहले मुझे न्याय दीजिए', इमरान खान की पाकिस्तानी न्यायाधीशों से गुहार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के तीन शीर्ष न्यायाधीशों से उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है और न्याय मिलने में देरी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। खान ने न्यायाधीशों से कहा, 'देर होने से पहले मुझे न्याय दीजिए। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, संघीय संवैधानिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र को उनके वकील सलमान सफदर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया। खान ने आरोप लगाया कि जेल में उनके संवैधानिक अधिकारों और कारागार नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उन्हें परिवार और वकीलों से मिलने, किताबें पढ़ने तथा टेलीविजन देखने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। खान के मुताबिक, 10 फरवरी 2026 को उनके वकील से मुलाकात के दौरान पता चला कि उनकी दाहिनी आंख की 85 प्रतिशत रोशनी जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस साल उन्हें वकीलों से केवल चार बार मिलने दिया गया, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सिर्फ एक बार कानूनी सलाहकार से मिलने की अनुमति मिली। उन्होंने पत्नी की आंखों की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जताई। खान के अनुसार, अप्रैल में बुशरा बीबी की आंख की जटिल सर्जरी हुई थी, लेकिन उन्हें दोबारा एकांत कारावास में भेज दिया गया। उन्होंने आशंका जताई कि उचित इलाज नहीं मिलने पर उनकी आंखों की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है। इमरान ने 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराने और विशेषज्ञों से जांच कराने के निर्देश का अब तक पालन नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि उनका रक्तचाप 193 तक पहुंच गया है और डॉक्टरों ने मस्तिष्क में रक्तस्राव तथा हृदयाघात का खतरा बताया है। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान ने कहा कि वह कोई विशेष रियायत नहीं, बल्कि अपने और पत्नी के लिए इलाज तथा अदालत के आदेशों का पालन चाहते हैं।

चीन में गुरुवार को मिलेंगे पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप, क्रेमलिन ने जताई बड़े प्रभाव की उम्मीद



मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को चीन में होने वाली प्रस्तावित बैठक का वैश्विक मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। क्रेमलिन ने सोमवार को यह बात कही। तीनों नेता चीन के शेनझेन शहर में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) मंच के शिखर सम्मेलन के दौरान एक साथ बैठक करेंगे। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने पत्रकारों को बताया कि यह मुलाकात चीनी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर होगी। उशाकोव ने कहा कि इस बैठक के महत्व और प्रतीकात्मक संदेश को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनके मुताबिक, यह अपनी तरह की पहली बैठक होगी। उन्होंने बताया कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तीनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना के अनुरूप आयोजित करने पर सहमति बनी है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में तीनों देशों के योगदान और उनके सहयोग पर भी जोर दिया जाएगा। उशाकोव ने कहा कि तीनों पक्ष इन सकारात्मक और रचनात्मक पहलुओं को आधार बनाकर सार्थक तथा विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन का मानना है कि इस बातचीत का समग्र अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के विकास पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।

बालेन्द्र शाह के भारत दौरे से पहले एयर रूट पर नई कूटनीतिक पहल

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के प्रस्तावित भारत दौरे से पहले दोनों देशों के बीच हवाई मार्ग (एयर रूट) को लेकर नई कूटनीतिक पहल हुई है। नेपाल लंबे समय से भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चार अतिरिक्त एयर रूट की अनुमति मांगता रहा है। इस बीच पहली बार भारत ने भी नेपाल के सामने अपने हवाई क्षेत्र से जुड़े दो एयर रूट की मांग की है। भारत ने रक्सौल और बागडोगरा के लिए नेपाली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। दोनों देशों के बीच एयर रूट को लेकर आपसी सहमति बनाने की संभावनाएं बढ़ी हैं। नेपाल फिलहाल बागडोगरा एयर रूट के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने को तैयार दिखाई दे रहा है। इसके बदले भारत भी उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा के रास्ते अंतरराष्ट्रीय विमानों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाता नजर आ रहा है।

नेपाल चार एयर रूट की मांग करता रहा है। इनमें बनबसा-महेन्द्रनगर, गोरखपुर-भैरहवा, सीतामढ़ी-जनकपुर और बागडोगरा-चंद्रगढ़ी एयर रूट शामिल हैं। इनकी अनुमति मिलने से नेपाल के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अधिक सुविधाजनक हो सकेगा। भैरहवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए गोरखपुर-भैरहवा एयर रूट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल का मानना है कि इस रूट की अनुमति मिलने से भैरहवा हवाई अड्डे का अंतरराष्ट्रीय उपयोग बढ़ेगा और भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी। दूसरी ओर, भारत ने



कूटनीतिक बातचीत के दौरान पहली बार नेपाल से रक्सौल और बागडोगरा के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। भारतीय पक्ष का प्रस्ताव है कि बागडोगरा और रक्सौल से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नेपाली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की सुविधा मिले।

दो दिन पहले नई दिल्ली में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक मुकेश डंगोल सहित नेपाली अधिकारियों की टीम ने इस प्रस्ताव पर प्रारंभिक गृहकार्य किया था। बातचीत के दौरान नेपाली पक्ष ने फिलहाल बागडोगरा एयर रूट के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं, जबकि रक्सौल के मामले में और अध्ययन करने की जरूरत बताई है। डंगोल ने कहा, 'रक्सौल के मामले में हमने कुछ समय तक अध्ययन करने की जरूरत होने की बात कही है। फिलहाल बागडोगरा के लिए हम सहमत हैं, ऐसा माना जा सकता है। मंगलवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गणेश पौडेल के भारत दौरे के दौरान भी इस विषय पर आगे बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एयर रूट को लेकर किसी समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है। नेपाल की ओर से बागडोगरा एयर रूट के लिए सकारात्मक संकेत दिए जाने के पीछे दोनों देशों के बीच आपसी लेन-देन के आधार पर सहमति बनाने की कोशिश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल चाहता है कि भारत भी उत्तराखंड से लगी सीमा यानी बनबसा-महेन्द्रनगर क्षेत्र के रास्ते अंतरराष्ट्रीय विमानों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति देने पर सकारात्मक फैसला करे। इससे नेपाल को लंबे समय से उठाए जा रहे पश्चिमी एयर रूट के मुद्दे पर राहत मिल सकती है। नेपाल के लिए भैरहवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिहाज से भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। इसी तरह महेन्द्रनगर के रास्ते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रवेश की अनुमति मिलने से नेपाल को पश्चिमी क्षेत्र में एक वैकल्पिक हवाई मार्ग उपलब्ध हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए उड़ान भरने वाले कुछ विमान बागडोगरा के रास्ते आते-जाते हैं और उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। इसलिए नेपाल की ओर से इस रूट के इस्तेमाल की अनुमति देना व्यावहारिक रूप से संभव दिखाई देता है। हालांकि, नेपाल की चिंता यह भी है कि भारतीय विमानों की उड़ानें नेपाली हिमालय के बहुत करीब से अधिक संख्या में संचालित न हों। इसके लिए नेपाल भारत का सहयोग चाहता है। भारत की ओर से मांगे गए रक्सौल एयर रूट के संबंध में नेपाल ने फिलहाल कोई अंतिम सहमति नहीं दी है।

थाईलैंड के फुकेत प्रांत में आग लगने से 11 लोगों की मौत



फुकेत (थाईलैंड)। थाईलैंड के प्रमुख प्रांत फुकेत में सोमवार तड़के काथू जिले के ताम्बोन पातोंग में आग लगने से पांच दुकानें (शॉपहाउस) जलकर खाक हो गईं। धुएं और आग की लपटों में फंसकर 11 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य झुलस गए। यह घटना राजधानी बैंकॉक से लगभग 860 किलोमीटर दक्षिण में हुई है। फुकेत थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। यह देश के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अंडमान सागर में स्थित है। बैंकॉक पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आग फांगमुआंग साई कोर रोड पर सोमवार तड़के करीब 3:15 बजे लगी। सड़क किनारे लगा ट्रांसफॉर्मर फट गया और आग की लपटें मोटरसाइकिल किराये पर देने वाली दुकान के सामने स्थापित फ्यूल डिस्पेंसर (ईंधन मशीन) तक पहुंच गईं। मृतकों में आठ महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। झुलसे लोगों में 12 महिलाएं और चार पुरुष हैं। इनमें से एक व्यक्ति म्यांमार और बाकी सभी थाईलैंड के थे। फुकेत पुलिस कमांडर मेजर जनरल सुराचाई सुकसाई ने बताया कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। उन्होंने आग लगाए जाने की संभावना को खारिज कर दिया है। फुकेत के गवर्नर चोटेनरिन केर्डसोम ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि तूफान के दौरान मोटरसाइकिल की दुकान के सामने लगे सब स्टेशन के बिजली के खंभे पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा।

भारत, चीन और इजराइल के लिए नियुक्त नेपाल के नए राजदूतों को राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ



काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने सरकार की सिफारिश पर तीन देशों के लिए नेपाल के नए आवासीय राजदूतों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने भारत, चीन और इजराइल के लिए नए राजदूत नियुक्त करते हुए सोमवार को उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार राष्ट्रपति पौडेल ने भारत के लिए डॉ. निश्चलनाथ पांडेय, चीन के लिए डॉ. कल्याण राज शर्मा और इजराइल के लिए सुरेश कुमार कर्ण को नेपाल का आवासीय राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्तियां नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 282 की उपधारा (1) के तहत की गई हैं। संविधान के इस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति नेपाल सरकार और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विदेशों में नेपाल के राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति पौडेल ने सोमवार को ही काठमांडू स्थित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में एक विशेष समारोह के दौरान तीनों नवनियुक्त राजदूतों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीन महत्वपूर्ण देशों में राजदूतों की नियुक्ति को नेपाल की कूटनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों में नए राजदूतों की नियुक्ति से दोनों देशों के साथ नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों, कूटनीतिक संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन राजदूतों पर होगी। इजराइल में नियुक्त राजदूत नेपाल और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा सहयोग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

नेपाल के उत्तरवाहिनी कालीगंडकी क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के पाल्पा और स्याडजा जिले की सीमा के पास स्थित उत्तरवाहिनी कालीगंडकी क्षेत्र को धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है। इस क्षेत्र में अब तक करीब 25 करोड़ नेपाली रुपये के निवेश से विभिन्न धार्मिक और शैक्षणिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान का नेतृत्व करने वाले कालीगंडकी ज्ञान-विज्ञान प्रतिष्ठान के संस्थापक आचार्य चैतन्यकृष्ण ने इस क्षेत्र को भारत सहित दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक गंतव्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत पाल्पा जिले के असेर्दी और स्याडजा जिले के मालुंगा क्षेत्र को उत्तरवाहिनी आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।



आचार्य चैतन्यकृष्ण ने करीब 11 वर्ष पहले इस क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य से प्रतिष्ठान की स्थापना की थी। इसके बाद से यहां धार्मिक गतिविधियों के विस्तार और आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर काम किया जा रहा है। उनका उद्देश्य उत्तरवाहिनी क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। आचार्य चैतन्यकृष्ण के अनुसार भारत के बनारस में भागीरथी गंगा नदी लगभग डेढ़ किलोमीटर तक उत्तर दिशा में बहती है। इसी विशेषता के कारण बनारस विश्वप्रसिद्ध धार्मिक स्थल बना हुआ है, लेकिन पाल्पा और स्याडजा के बीच कालीगंडकी नदी करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक उत्तर दिशा में बहती है। उनका कहना है कि दुनिया में इतनी लंबी दूरी तक उत्तरवाहिनी बहने वाली नदी के रूप में कालीगंडकी की विशेष पहचान है। यदि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, तो भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों से लाखों हिंदू श्रद्धालुओं को हर साल यहां आकर्षित किया जा सकता है। उत्तरवाहिनी क्षेत्र को व्यवस्थित धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

इनमें विशाल शालग्राम मंदिर का निर्माण, गुरुकुल का संचालन, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना और 108 धाराओं का निर्माण प्रमुख हैं। चैतन्यकृष्ण के मुताबिक विशाल शालग्राम मंदिर निर्माण, गुरुकुल के लिए अक्षय कोष की स्थापना, जमीन का विस्तार और 108 धाराओं के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। इस अभियान के तहत धार्मिक कार्यक्रमों से प्राप्त स्वैच्छिक दान की राशि का उपयोग करते हुए अब तक 90 रोपनी जमीन खरीदी गई है, जो प्रतिष्ठान के स्वामित्व में है। इस क्षेत्र में अब तक करीब 25 करोड़ नेपाली रुपये के निवेश से विभिन्न धार्मिक और शैक्षणिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें कालीगंडकी गुरुकुल और 10 बिस्तरों वाला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल प्रमुख हैं। चैतन्यकृष्ण के नेतृत्व में संचालित गुरुकुल में 'संस्कार के साथ आविष्कार' को मुख्य आदर्श बनाया गया है। उनका मानना है कि संस्कारयुक्त शिक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के बीच संतुलन स्थापित करके ही शांतिपूर्ण समाज तथा अच्छे और जिम्मेदार नागरिक तैयार किए जा सकते हैं।

नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात बंद, अब जून से फिर होगी आपूर्ति

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल ने बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात फिलहाल बंद कर दिया है। दोनों देशों के बीच हुए पांच वर्षीय बिजली निर्यात समझौते की निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद इस साल के लिए बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। अब अगले साल ही नेपाल से बांग्लादेश को दोबारा बिजली निर्यात किया जाएगा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच 2 अक्टूबर, 2022 को मानसून के दौरान बिजली निर्यात के लिए पांच साल का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक छह महीने की अवधि में प्रतिदिन 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जाती थी। समझौते के अनुसार इस साल रविवार तक 40 मेगावाट बिजली का निर्यात किया गया। निर्धारित अवधि समाप्त होने के साथ ही अब आपूर्ति रोक दी गई है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि अब अगले साल ही बांग्लादेश को बिजली निर्यात किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुष्क मौसम शुरू होने के कारण फिलहाल नेपाल के पास निर्यात के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है। श्रेष्ठ के मुताबिक त्योहारों और छुट्टियों का समय समाप्त होने के बाद मंगलवार से औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में बिजली की मांग बढ़ने लगेगी। अभी बिजली प्रणाली में मांग लगभग 1,800 से



1,900 मेगावाट है, जो बढ़कर 2,400 से 2,500 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि फिलहाल नेपाल में बिजली की उपलब्धता लगभग 2,600 से 2,700 मेगावाट है। ऐसे में घरेलू मांग बढ़ने के साथ भारत को होने वाला बिजली निर्यात भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा। श्रेष्ठ ने कहा कि अगले सात से दस दिनों के भीतर नेपाल को भारत से बिजली आयात करने की जरूरत पड़ सकती है। इस साल नेपाल से बांग्लादेश को बिजली निर्यात पहले भी बाधित हुआ था। 26 अगस्त को भोटेकोशी में आई भीषण बाढ़ से त्रिशूली कॉरिडोर के जलविद्युत प्रोजेक्टों को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके कारण भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली 40 मेगावाट बिजली का निर्यात रोकना पड़ा था। बाढ़ से बांग्लादेश को बिजली निर्यात की अनुमति प्राप्त त्रिशूली और चिलिमे जलविद्युत केंद्र प्रभावित हुए थे। इसके बाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से दूसरे जलविद्युत केंद्रों से उत्पादित बिजली बांग्लादेश भेजने की अनुमति प्राप्त की। इसके बाद बांग्लादेश को बिजली निर्यात फिर से शुरू किया गया था।

हालांकि, अब समझौते की समयसीमा समाप्त होने और नेपाल में बिजली की घरेलू मांग बढ़ने के कारण निर्यात दोबारा रोक दिया गया है। नेपाल ने पिछले सितंबर महीने में भारत को बिजली बेचकर 592 करोड़ 50 लाख नेपाली रुपये का कारोबार किया था। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के विद्युत प्रणाली संचालन विभाग (लोड डिस्पैच सेंटर) के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में भारत को कुल 63 करोड़ 39 लाख 86 हजार 8 यूनिट बिजली निर्यात की गई थी। पिछले साल सितंबर में भारत को बिजली निर्यात से 496 करोड़ 30 लाख रुपये का कारोबार हुआ था। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस साल सितंबर में बिजली निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हुई है।

आसियान और ऑस्ट्रेलिया व्यापार, शिक्षा व समुद्री सुरक्षा में बढ़ाएंगे सहयोग

मनीला। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार, शिक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में सहयोग और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। फिलीपींस की सरकारी न्यूज एजेंसी पीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर ने सोमवार को फिलीपीन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित छठे आसियान-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आसियान के पहले संवाद साझेदार के रूप में ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सतत विकास को आगे बढ़ाने में साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबले, मानव तस्करी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 197.5 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी 'ऑस4आसियान फ्यूचर्स इनिशिएटिव' के माध्यम से क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा बदलाव और आसियान पावर ग्रिड को समर्थन दे रहा है। इसके अलावा उसने दक्षिण-पूर्व एशिया में ऊर्जा के लिए क्षेत्रीय संपर्क कोष में भी भागीदारी की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आसियान सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड इमर्जिंग डिजीजेज को 1.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सहायता देने की ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आपदा प्रबंधन और प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के प्रयासों में भी सहयोग कर रहा है। मार्कोस ने कहा कि अगले पांच वर्षों में साझा प्रतिबद्धताओं को ऐसी उपलब्धियों में बदलना होगा, जिनका लाभ क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक मिल सके।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आसियान को निरंतर समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा की संभावनाओं का लाभ उठाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता विकसित करने, बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षा के समान अवसर और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अल्बनीज ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के प्रभावों और इतिहास के सबसे बड़े तेल एवं ऊर्जा संकट से निपटने के लिए साझा ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने में निवेश करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आसियान के डिजिटल परिवर्तन को गति देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए डिजिटल सहयोग पैकेज की भी घोषणा की। इसके तहत क्षेत्र के डिजिटल तंत्र को मजबूत करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित उपयोग के मानक विकसित करने और डिजिटल कार्यबल तैयार करने में मदद की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यवधानों के बीच आसियान और दक्षिण-पूर्व एशिया का विश्वसनीय साझेदार बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराई।

एक नजर

उत्तर प्रदेश में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ डाला छठ महापर्व का समापन, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब



लखनऊ,एजेंसी। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ का सोमवार को पूरे उत्तर प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ समापन हुआ। पर्व के चौथे और अंतिम दिन भोर में लाखों व्रती महिलाओं ने नदियों, तालाबों, सरोवरों और जलाशयों के तट पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसी के साथ 36 घंटे तक चलने वाला निर्जला व्रत संपन्न हुआ। सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना के लिए प्रदेशभर के घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। हर ओर छठी मइया के पारंपरिक गीतों, शंखध्वनि और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया सहित प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा और झांसी तक छठ महापर्व की अनुपम छटा देखने को मिली। भोर होने से पहले ही व्रती महिलाएं अपने परिजनों के साथ गंगा, गोमती, सरयू, वरुणा, चंद्रप्रभा, रामगंगा और सोन सहित विभिन्न नदियों के घाटों पर पहुंच गई थीं। ईख, फल, दीपक और पूजन सामग्री से सजे दउरे लेकर घाटों पर पहुंचीं महिलाओं ने विधि-विधान से छठी मइया की पूजा-अर्चना की। अरुणोदय के साथ ही व्रतियों ने दूध और जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की।

प्रदेश के प्रमुख नदियों के घाटों के साथ ही तालाबों, सरोवरों और ग्रामीण क्षेत्रों के जलाशयों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कई स्थानों पर सुबह होते-होते घाटों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची। काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ की नगरी में डाला छठ की भव्यता देखते ही बनी। दशाश्वमेध, अस्सी, पंचगंगा, सामने घाट, तुलसी घाट, हनुमान घाट, सिंधिया घाट और भैसासुर घाट सहित गंगा के विभिन्न तटों पर हजारों व्रती महिलाएं पूरी रात छठी मइया की आराधना में लीन रहीं। ओस और ठंड के बावजूद महिलाओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। घाटों पर 'उग हो सूरज देव, भइल अरघ के बेर' और 'पुरुबे से उगले नारायण' जैसे पारंपरिक छठ गीतों की मधुर गूंज रातभर सुनाई देती रही। जैसे ही पूरब दिशा में सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी, व्रती महिलाएं जल में खड़े होकर अर्घ्य देने की तैयारी में जुट गईं। सूर्यदेव के उदय होते ही जयकारों और आतिशबाजी से गंगा घाट गूंज उठे। महिलाओं ने पूरे विधि-विधान से अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण किया। इसके बाद प्रसाद वितरण और एक-दूसरे को छठ पर्व की शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट के अलावा बलुआघाट, शिवकुटी, अरैल और फाफामऊ घाटों पर हजारों व्रती महिलाओं ने परिवार के साथ पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं, राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के लक्ष्मण मेला घाट, कुड़ियाघाट, झूलेलाल घाट और संझियाघाट पर छठ पूजा की विशेष रौनक रही। यहां महिलाओं ने छठी मइया की पूजा कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। वाराणसी के गंगा घाटों पर छठ पूजा का अलौकिक दृश्य देखने पहुंचे विदेशी पर्यटक भी भारतीय संस्कृति और व्रती महिलाओं की अटूट आस्था से अभिभूत नजर आए। घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पारंपरिक पूजा पद्धति और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दृश्य ने उन्हें खासा आकर्षित किया। कई विदेशी पर्यटकों ने इस धार्मिक अनुष्ठान की तस्वीरें खींचीं और अपने कैमरों में इस अद्भुत दृश्य को कैद किया। छठ पूजा के समापन के बाद वाराणसी के घाटों पर एक और पारंपरिक दृश्य देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने घर लौटने से पहले अपनी मांग से नाक तक गहरा नारंगी सिंदूर लगाया। इसके बाद उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी सिंदूर लगाया। इस दौरान व्रती महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रही। सिर पर साड़ी का पल्लू और मांग से नाक तक सजा नारंगी सिंदूर व्रती महिलाओं की विशेष पहचान बना रहा। ज्योतिविद आचार्य उदयनाथ तिवारी के अनुसार, डाला छठ में मांग से नाक तक सिंदूर लगाने की परंपरा सौभाग्य, समर्पण और आस्था का प्रतीक मानी जाती है।

बदरीनाथ के कपाट बंद होने के साथ चारधाम यात्रा संपन्न, 23.49 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

बदरीनाथ,एजेंसी। भगवान बदरीविशाल के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सोमवार रात 9 बजकर 37 मिनट पर बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखंड के चारों धामों की इस वर्ष की ग्रीष्मकालीन यात्रा संपन्न हो गई। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था और सेना के बैंड की धुनों के बीच धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया।

कपाट बंद होने से पहले सुबह ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर के द्वार खोले गए। भगवान का अभिषेक और श्रृंगार कर नियमित दर्शन शुरू हुए। दिनभर श्रद्धालुओं ने भगवान बदरीविशाल के दर्शन किए। शाम आठ बजे से कपाट बंद करने की विशेष प्रक्रिया शुरू हुई। रावल अमरनाथ नंबूदरी ने परंपरा के अनुसार स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी को उनके मंदिर से भगवान बदरीविशाल के गर्भगृह में विराजमान कराया। इसके बाद भगवान की निर्वाण मूर्ति को घृत कंबल ओढ़ाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रात 9:37 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। रविवार को हुई बारिश और बर्फबारी के बाद धाम में ठंड बढ़ गई थी। आसपास की चोटियों पर बर्फ जमी रही,हालांकि सोमवार को मौसम साफ होने से श्रद्धालुओं को राहत मिली। कपाट बंद होने के मौके पर सेना और दानदाताओं की ओर से भंडारे



भी लगाए गए। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष 23.49 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बदरीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने यात्रा से जुड़े सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, विजय कप्रवाण और मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने भी यात्रा के सफल संचालन में सहयोग देने वाले विभागों, संस्थाओं और तीर्थ पुरोहितों का आभार जताया। पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में होगी शीतकालीन पूजा: कपाट बंद होने के बाद मंगलवार को भगवान उद्धव और कुबेर की उत्सव डोलियां सेना के बैंड के साथ योग बदरी पांडुकेश्वर के लिए रवाना होंगी। यहां शीतकाल में दोनों देवताओं की पूजा-अर्चना होगी। वहीं, भगवान गरुड़ की प्रतिमा और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी ज्योतिर्मठ स्थित नृसिंह मंदिर पहुंचेगी। गरुड़ जी मंगलवार को सीधे ज्योतिर्मठ रवाना होंगे,जबकि रावल और नायब रावल शंकराचार्य की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर में प्रवास करेंगे। 18 नवंबर को शंकराचार्य की गद्दी ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर में विराजमान होगी। बदरीनाथ धाम में 12 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू हो गई थीं। 15 नवंबर को माता लक्ष्मी को कढ़ाई भोग अर्पित किया गया और उन्हें गर्भगृह में विराजमान होने का निमंत्रण दिया गया। इससे पहले आदि केदारेश्वर सहित अन्य सहवर्ती मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए थे। सोमवार को माता मूर्ति मंदिर और भविष्य बदरी सुभाई के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।

अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ ज़ोन प्रवीण कुमार ने की मेला तैयारियों की समीक्षा

अयोध्या। परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेला में लगे समस्त सुपर जोनल,जोनल,सेक्टर ,स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारीगण की पुलिस लाइन अयोध्या में संयुक्त ब्रीफिंग अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ ज़ोन प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक सोमेन बर्मा, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर द्वारा की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ ज़ोन प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार व पुलिस उप महानिरीक्षक सोमेन बर्मा ने परिक्रमा मेला में लगे समस्त सुपर जोनल/जोनल/सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारीगण को ब्रीफ करते हुये कहा कि सभी मजिस्ट्रेट अपने ड्यूटी स्थल पर समय से पूर्व पहुंचे तथा उन्हें अपने तैनाती क्षेत्र के समीपस्त समस्त जानकारियां यथा-एम्बुलेंस व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर, खोया पाया केन्द्र, पेयजल व्यवस्था आदि की जानकारी कर ले। अपने तैनाती क्षेत्र की संवेदनशील स्थानों यथा-सकरा स्थान, पुलिया, निर्माणाधीन कार्य स्थल इत्यादि जहां पर भी बेरीकेटिंग की गयी है आदि को देख ले और यदि कहीं पर भी और वैलिडेटिंग करने की आवश्यकता है तो उसे संबंधित से समन्वय कर समय पर करवा लें। सभी मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी अपनी तैनाती क्षेत्र के स्थानीय निवासियों से भी सम्पर्क कर उनसे सौहार्द बनायें, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में उनकी मदद ली जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी अपनी तैनाती सेक्टर के सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के प्रभारी होंगे। उन्होंने कहा कि सभी तैनात मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारियां होनी चाहिए तथा रेलवे क्रासिंग पर तैनात अधिकारीगण विशेष ध्यान रखेंकि क्रासिंग पर लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हों, बेरीकेटिंग मजबूत रहें तथा क्रासिंग के स्थानों पर रात्रि के समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि सभी अधिकारीगण अपने तैनाती क्षेत्र का आज रात्रि में पुन: जायजा ले लें और यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसे दूर कर लें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लें कि किस स्थान पर किस प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने कहा कि जिन-जिन स्थान पर भीड़ अधिक एकत्रित होने की संभावना हो वहां पर उसे मैनेज करने हेतु तैयारी पूर्व से ही कर ली जाए। उन्होंने कहा कि विगत परिक्रमा के दौरान जो भी समस्याएं आई थी उनसे सीख लेते हुए इस परिक्रमा में किसी भी प्रकार की समस्या ना आने पाए उसकी तैयारी पूर्ण रखें।

काजीरंगा हादसा: मुख्यमंत्री ने 12-सूत्रीय सड़क सुरक्षा योजना की घोषणा की

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को काजीरंगा में हुए सड़क हादसे, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, को देखते हुए सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 12-सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की। इन उपायों में कमर्शियल वाहनों में स्पीड-लिमिटिंग डिवाइस (गति सीमित करने वाले उपकरण) लगाना अनिवार्य करना, तेज रफ्तार और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जांच तेज करना, और बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के परमिट रद्द करना शामिल है। डॉ. सरमा ने बताया कि यह योजना ट्रैफिक, परिवहन और आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक समीक्षा बैठक में तैयार की गई है। बैठक में काजीरंगा हादसे की समीक्षा की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई।

सोशल मीडिया पर इस योजना की घोषणा करते हुए डॉ. सरमा ने कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाएगा और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सोमवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर उन्होंने लिखा, 'रविवार की देर रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में, हमने सड़क सुरक्षा पर एक 12-सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है। इसे सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि हमारी सड़कें और लोग सुरक्षित रहें। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पहला उपाय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिला-स्तरीय सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स को सक्रिय करना है। सरकार सभी कमर्शियल वाहनों में स्पीड-लिमिटिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य करेगी और इनके साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच ट्रैफिक जांच तेज की जाएगी, जिसमें तेज रफ्तार, लापरवाही से गाड़ी चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इस योजना में दुर्घटना संभावित स्थानों (एक्सीडेंट-प्रोन स्पॉट्स) की पहचान करना और वहां पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग व ट्रैफिक सिग्नल लगाना, लाइटिंग में सुधार करना और सड़क डिवाइडरों की मरम्मत करना भी शामिल है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को और सख्त बनाएगी ताकि आवेदकों के ड्राइविंग कौशल और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति उनकी समझ को परखा जा सके। साथ ही, हर सड़क दुर्घटना का विश्लेषण किया जाएगा ताकि उसके कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। एक अन्य उपाय के तहत 'जीरो-फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम' (शून्य मृत्यु दर जिला कार्यक्रम) शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य, समय-सीमा और जवाबदेही तय की जाएगी। इस योजना में हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू करने की बात भी कही गई है—जिसमें पीछे बैठने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार की विरासत और विकास की झलक, बिहार पवेलियन का भव्य उद्घाटन

55 से अधिक स्टॉलों में प्रदर्शित हो रहे बिहार के हस्तशिल्प, कला, संस्कृति, औद्योगिक उत्पाद और निवेश की संभावनाएं

एम.जबिउल्लाह, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में पार्टनर स्टेट बिहार के पवेलियन का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार एवं दिल्ली में बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव पलका साहनी भी मौजूद रहीं।

भारत मंडपम के हॉल नंबर-2 में स्थापित बिहार पवेलियन को इस वर्ष मेले की थीम 'विकास और विरासत' (Development and Heritage) के अनुरूप आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहां बिहार की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और आधुनिक औद्योगिक विकास की झलक देखने को मिल रही है। उद्घाटन के बाद अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों एवं हस्तशिल्प की सराहना की। इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से देश-विदेश से आने वाले आगंतुकों, उद्यमियों और निवेशकों को बिहार पवेलियन में आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ-साथ औद्योगिक विकास और निवेश की नई संभावनाओं को भी प्रदर्शित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में निवेश और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। ट्रेड फेयर निवेशकों और उद्यमियों के लिए बिहार के औद्योगिक इकोसिस्टम तथा उपलब्ध अवसरों को



समझने का महत्वपूर्ण मंच है।

कुंदन कुमार ने बताया कि बिहार पवेलियन में राज्य की कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत के साथ औद्योगिक विकास को भी प्रमुखता दी गई है। बिहार म्यूजियम की विशेषताओं से परिचित कराने के लिए अलग गैलरी बनाई गई है। वहीं निवेश और उद्योग से संबंधित स्टॉल के माध्यम से संभावित निवेशकों को राज्य में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बिहार पवेलियन में 55 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें राज्य की विरासत से जुड़ी वस्तुओं, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय औद्योगिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य बिहार के उद्यमियों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना, उनके उत्पादों की पहुंच बढ़ाना और उन्हें बाजार की मांग एवं संभावनाओं से परिचित कराना है। इस वर्ष बिहार पवेलियन के माध्यम से पारंपरिक विरासत और आधुनिक औद्योगिक संभावनाओं के बीच बेहतर समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यहां आने वाले आगंतुकों को बिहार के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों की जानकारी मिल रही है। बिहार पवेलियन केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान और उपलब्धियों का प्रदर्शन स्थल ही नहीं, बल्कि निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच संवाद तथा नए व्यावसायिक अवसरों को विकसित करने का मंच भी बन रहा है।

समाज को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं संत: डॉ. मोहन यादव

भोपाल,एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संत दर्शन से हमारे भाग्य का उदय होता है। समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य संत करते है। जनकल्याणकारी कार्यों और जनसेवा के दायित्वों का निर्वहन करते हुए संतों का सानिध्य हमें संबल और प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन और शासन के कार्यों में संतों का आशीर्वाद हमें निरंतर सद्कार्य करने की शक्ति देता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार देर शाम इंदौर प्रवास के दौरान क्लर्क कॉलोनी स्थित दिगम्बर जैन मंदिर इंदौर में जैन मुनि सुधाकर सागर के सानिध्य में आयोजित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिये परम सौभाग्य का है क्योकि मुझे संतों की वाणी सुनने को मिल रही है। इससे शब्द ही नहीं काया भी पवित्र होती है। भगवान महावीर स्वामी के बताए मार्ग पर चलकर जैन समाज काफी समृद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन संत मुनि सुधाकर महाराज मनुष्यों को सदकर्मो की शिक्षा देकर उन्हें संस्कारित कर रहे है। मनुष्य निर्माण का यह कार्य अभिनंदनीय है। हमारा समाज व्यसन से बचे और अच्छे कार्यों में लगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये लगातार कार्य कर रही है। गौपालन को बढ़ावा देने के साथ गौपालक को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंन कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश भर में आयुर्वेद कॉलेज और चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। कार्यक्रम में संत जैन सुधासागर महाराज ने कहा भारत ऐसा देश है



जहां सभी धर्म और सम्प्रदायों का सम्मान किया जाता है और घर-घर में गौपालन होते है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जैन संत मुनि का आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन संत मुनि ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अभिमंत्रित कलश भेंट किया। कार्यक्रम में विधायक रमेश मेंदोला, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, सुमित मिश्र, श्रवण सिंह चावड़ा, हरिनारायण यादव सहित जैन संत मुनि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को इंदौर में श्रीमद् विजय नित्यसेनसूरीश्वरजी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद गुरुवर एवं संत समाज के आशीर्वाद से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने सामाजिक अनुशासन और जनहित को ध्यान में रखते हुए खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता, मर्यादा और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौपालन, प्राकृतिक खेती और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए गीता भवन जैसे संस्थानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विशेषता उसकी सर्वधर्म सद्भाव की भावना है। दुनिया के अनेक देश एक धर्म की विचारधारा के आधार पर संचालित होते हैं, जबकि भारत ऐसा देश है जो सभी धर्मों, विचारों और परंपराओं का सम्मान करता है। विभिन्न विचारधाराओं से निकलने वाले अमृतमय विचारों को आत्मसात करना ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मुख्यमंत्री ने महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद प्रदेश सरकार को निरंतर मिलता रहे, ताकि सरकार जनकल्याण और समाजहित के कार्यों को और अधिक गति से आगे बढ़ा सके। उन्होंने इंदौर श्रीसंघ का भी अभिनंदन किया तथा परम पूज्य गुरुवर के चरणों में पुन: वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार देर शाम अपने इंदौर प्रवास के दौरान स्थानीय नृसिंह वाटिका पहुंचकर अनुष्ठान आराधिका महासती साध्वी कुमुदलता से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साध्वी श्री का अभिवादन कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साध्वी श्री के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में संत-महात्माओं तथा आध्यात्मिक गुरुओं का सदैव विशिष्ट स्थान रहा है। संतों का सान्निध्य एवं उनका मार्गदर्शन समाज को नैतिक मूल्यों, सदाचार, सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राजनांदगांव से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन रवाना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का सपना निरंतर साकार हो रहा है। इसी क्रम में आज सोमवार को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। तीर्थयात्रियों के चेहरों पर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन की खुशी और उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दी।

राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा, राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, कोमल सिंह राजपूत, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी एवं खुबचंद पारख ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने तीर्थयात्रियों को सुखद, मंगलमय और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित श्री



रामलला दर्शन योजना प्रदेशवासियों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। भगवान श्रीराम का छत्तीसगढ़ से गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है। यहां के जनजीवन, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत में भगवान श्रीराम के प्रति अगाध श्रद्धा समाहित है। ऐसे में श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। राज्य सरकार की इस पहल से उन श्रद्धालुओं को भी अयोध्या धाम की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है, जिनके लिए विभिन्न कारणों से स्वयं तीर्थयात्रा की व्यवस्था करना कठिन होता है। यह योजना श्रद्धालुओं की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं को भी सशक्त बना रही है। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम की तीर्थयात्रा निरंतर जारी है। योजना के तहत अब तक कुल 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में योजना के व्यापक क्रियान्वयन और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों के माध्यम से अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)